वर्ष 13 • अंक 17 • 14 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

शुक्रवार 6 मार्च 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 6

कपास-धागे की कीमतों में नरमी

पीयूष गोयल ▸▸ पृष्ठ 4

जीईएम पोर्टल पर रेल एवं रक्षा खरीद जल्द

डॉलर रु. 73.30 ▲ 10 पैसे | यूरो रु. 81.90 ▲ 30 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 43199 ▲ 69 रुपये | सेंसेक्स 38470.60 ▲ 61.10 | निफ्टी 11269.00 ▲ 18.00 | निफ्टी फ्यूचर्स 11255.30 ▼ 13.70 | ब्रेंट क्रूड 50.90 डॉलर ▼ 0.70 डॉलर

एक नज़र

कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.5 प्रतिशत ब्याज

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने गुरुवार को चालू वित्त वर्ष (2019-20) के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर घटाकर 8.5 प्रतिशत करने की घोषणा की है। यह पिछले 7 वर्षों का न्यूनतम स्तर है। ईपीएफओ ने पिछले वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर 8.65 प्रतिशत ब्याज दिया था। ईपीएफओ के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक में यह निर्णय लिया गया। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बैठक के बाद कहा कि ईपीएफओ ने सीबीटी की बैठक में 2019-20 के लिए भविष्य निधि जमा पर 8.5 प्रतिशत ब्याज देने का निर्णय किया है। पृष्ठ 4

एसबीआई कार्ड आईपीओ को 26 गुना बोलियां

एसबीआई कार्ड्स ऐंड पेमेंट सर्विसेस के सार्वजनिक आरंभिक निर्गम (आईपीओ) को करीब 2 लाख करोड़ रुपये मूल्य की बोलियां मिली हैं। आईपीओ में पेशकश किए गए 10 करोड़ शेयरों के मुकाबले 2.7 अरब बोलियां (26 गुना अधिक) आईं। धनाढ्य निवेशकों के लिए सुरक्षित(एचएनआई) हिस्से को 44 गुना बोलियां मिली, जबकि खुदरा खंड के लिए 2.5 गुना बोलियां आईं। बुधवार को आईपीओ की संस्थागत श्रेणी के लिए 57 गुना बोलियां आई थीं।

आरकॉम के लिए 23,000 करोड़ रु. की समाधान योजना

बैंकों ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के लिए 23,000 करोड़ रुपये की समाधान योजना मंजूर की है। इनमें 5,500 करोड़ रुपये चीन के बैंकों को मिलेंगे। इससे उनको उनका करीब 55 प्रतिशत मूलधन मिल जाएगा। इनमें चीन के वे बैंक भी शामिल है, जिन्हें कंपनी के प्रवर्तक अनिल अंबानी ने कथित तौर पर व्यक्तिगत गारंटी दी है। एक सूत्र ने कहा कि कर्जदाताओं की समिति ने रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस टेलीकॉम और रिलायंस इन्फ्राटेल पर बकाया कर्जा के निपटान योजना को सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दी। पृष्ठ 2

मोबाइल डेटा के लिए न्यूनतम कीमत का प्रस्ताव

दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो ने मोबाइल डेटा सेवाओं के लिए न्यूनतम निर्धारित मूल्य तय किए जाने की मांग की है। इन कंपनियों ने कहा है कि वॉइस कॉल दरों का निर्धारण बाजार पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इन कंपनियों ने कहा है कि डेटा दरों का नियमन दूरसंचार क्षेत्र की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए। एयरटेल ने कहा कि मोबाइल डेटा सेवाओं के लिए फ्लोर प्राइस (न्यूनतम निर्धारित कीमत) तय की जानी चाहिए। कंपनी ने डेटा सेवाओं के लिए न्यूनतम कीमत तीन संभावित विकल्पों के साथ दो वर्षों के लिए तय किए जाने का सुझाव दिया है। पृष्ठ 2

यकृत की गंभीर बीमारी के लिए जायडस दवा को मंजूरी

दवा कंपनी जाइडस कैडिला ने एक ऐसी दवा विकसित की है, जिससे शराब से इतर वजहों से होने वाली यकृत (लीवर) की गंभीर बीमारी ठीक हो सकेगी। भातीय दवा महानियंत्रक ने कंपनी की इस दवा को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने दावा किया है कि नॉन-सिरोटिक नॉन अल्कोहलिक स्टीयटोहेपेटाइटिस (नैस) के इलाज में इस्तेमाल होने वाली विश्व की यह पहली दवा होगी। पृष्ठ 3

येस बैंक को उबारने की कवायद

बैंक का बोर्ड भंग, ग्राहक नहीं निकाल सकेंगे 50 हजार रुपये से अधिक रकम

हंसिनी कार्तिक
मुंबई, 5 मार्च

फोटोः दलीप कुमार

- एसबीआई के पूर्व सीएफओ प्रशांत कुमार बनाए गए येस बैंक के प्रशासक
- एसबीआई और एलआईसी कर सकते हैं येस बैंक की मदद
- कॉल ऑप्शन के इस्तेमाल की समयसीमा 5 मार्च को समाप्त
- येस बैंक को हो चुका है 12,000 करोड़ रुपये का नुकसान
- आईडीबीआई के बाद एक और बैंक को बचाने के लिए आगे आई सरकार

संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के येस बैंक के जमाकर्ताओं और बॉन्डधारकों के हितों के संरक्षण के लिए एक योजना पर काम चल रहा है। बैंक के पूंजी जुटाने के सभी प्रयासों के नाकाम होने के बाद यह कदम उठाया जा रहा है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक येस बैंक के पुनर्गठन या विलय के लिए रिजर्व बैंक (आरबीआई) सरकार और सरकारी वित्तीय संस्थानों की मदद ले सकता है।

शुरुआती योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) येस बैंक को संकट से उबार सकते हैं। एलआईसी ने आईडीबीआई बैंक को संकट से उबारने के लिए 2018 में उसकी 51 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था। सूत्रों के मुताबिक येस बैंक के मामले में आरबीआई जमाकर्ताओं और बॉन्डधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कदम उठाना चाहता है।

हालांकि येस बैंक को उबारने की योजना के बारे में विस्तृत जानकारी का अभी इंतजार है लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इक्विटी की कीमत को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। इसमें बैलेंस शीट के पुनर्गठन को प्राथमिकता दी जाएगी। एक बैंकिंग सलाहकार ने कहा, 'आस्तियों को वास्तविक मूल्य पर लाने की जरूरत है और फिर पता चलेगा कि बैंक को कितनी पूंजी की जरूरत है।' एलआईसी ने इस बारे में बिज़नेस स्टैंडर्ड के सवालों का जवाब नहीं दिया लेकिन एसबीआई ने स्टॉक एक्सचेंजों को बताया कि वह इसका खुलासा करने में सूचीबद्धता के नियमों में निर्धारित समयसीमा का पालन करेगा।

सूत्रों ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि येस बैंक को 5 मार्च तक 80 करोड़ रुपये के एटी-1 बॉन्ड पर कॉल ऑप्शन का इस्तेमाल करना था। एक सूत्र ने कहा कि बैंक ने कॉल ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं किया है। बॉन्ड के भुगतान का दायित्व निभाने में नाकामी के कारण आरबीआई को आगे आना पड़ा है।

हाल ही में केयर रेटिंग्स ने येस बैंक के 21,016 करोड़ रुपये के बॉन्ड की रेटिंग घटाकर क्रेडिट वॉच के साथ नकारात्मक प्रभाव कर दिया था। इन बॉन्डों को नकारात्मक रेटिंग के साथ पहले ही जारी किया जा चुका है।

देसाई हरिभक्ति कंसल्टेंट्स के चेयरमैन शैलेश हरिभक्ति ने कहा, 'सरकसर एक और बड़े वित्तीय संस्थान को विफल होने देना नहीं चाहेगी।' येस बैंक की जमा 30 सितंबर, 2019 तक 2.09 लाख करोड़ रुपये थी, वहीं उसने कुल 2.24 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया हुआ है। वित्त वर्ष 2020 में बैंक को अब तक 12,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, वहीं इसने 30,000 करोड़ रुपये का कर्ज वॉच श्रेणी वाली संपत्तियों को दिया है।

हरिभक्ति की बात पर सहमति जताते हुए अश्विन पारेख एडवाइजरी सर्विसेज के मैनेजिंग पार्टनर अश्विन पारेख ने कहा कि जमा खाताधारकों के श्रेष्ठ हित में नियामकीय हस्तक्षेप बेहद आवश्यक है। हालांकि उनका मानना है कि येस बैंक को उबारने के लिए दिए जाने वाले पैकेज को समायोजित करने के लिए कई नियामकीय व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने कहा, 'ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के बाद से नियामकीय मोर्चे पर कई सारे बदलाव हो चुके हैं और योजना को एकसाथ पेश करना उतना आसान नहीं होगा।' येस बैंक दिसंबर तिमाही के नतीजे करीब एक महीने की देरी के बाद 14 मार्च को जारी कर सकता है।

बैंकों ने की शेयर स्वैप अनुपात की घोषणा

नम्रता आचार्य और अनूप रॉय
कोलकाता/मुंबई, 5 मार्च

- ओरिएंटल बैंक के प्रति 1,000 शेयरों के लिए 1,150 शेयर जारी करेगा पीएनबी
- यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के प्रति 1,000 शेयरों के बदले पीएनबी के मिलेंगे 121 शेयर
- आन्ध्रा बैंक के प्रति 1,000 शेयर के लिए यूनियन बैंक के 325 शेयर मिलेंगे
- कॉर्पोरेशन बैंक के प्रति 1,000 शेयर पर मिलेंगे यूनियन बैंक के 330 शेयर
- सिंडिकेट बैंक के प्रति 1,000 शेयर पर मिलेंगे केनरा बैंक के 158 शेयर

सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों के विलय को मंत्रिमंडल की हरी झंडी मिलने के बाद इन बैंकों के निदेशक मंडल ने भी मंजूरी दे दी और भारतीय स्टेट बैंक एवं बैंक ऑफ बड़ौदा की तर्ज पर चार बड़े बैंक बनाने के लिए शेयरों की अदला-बदली अनुपात योजना भी जारी कर दी।

10 बैंकों के विलय में पंजाब नैशनल बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एंकर बैंक की भूमिका में होंगे। विलय 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा। पिछले साल बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ था। इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में उसके सभी पांच सहायक बैंकों का विलय किया गया था, जिससे एसबीआई दुनिया के शीर्ष 50 बैंकों की सूची में शामिल हो गया था।

पंजाब नैशनल बैंक में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय होगा, जिससे यह भारतीय स्टेट बैंक के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक होगा। एक्सचेंज पर अधिसूचना के अनुसार पंजाब नैशनल बैंक ओरिएंटल बैंक के प्रति 1,000 शेयरों के लिए 1,150 शेयर जारी करेगा। इसी तरह यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के प्रति 1,000 शेयरों के बदले पंजाब नैशनल बैंक के 121 शेयर जारी किए जाएंगे।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आन्ध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय होना है। इस विलय के तहत आन्ध्रा बैंक के प्रति 1,000 शेयर के लिए यूनियन बैंक के 325 शेयर जारी किए जाएंगे, वहीं कॉर्पोरेशन बैंक के प्रति 1,000 शेयर पर यूनियन बैंक के 330 शेयर जारी किए जाएंगे।

बेंगलूरु मुख्यालय वाला केनरा बैंक सिंडिकेट बैंक के प्रति 1,000 शेयर पर 158 शेयर जारी करेगा। इसी तरह इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय होगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ज्यादा कुशल और बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बनाने के मकसद से बैंकों के एकीकरण योजना को मंजूरी दी है। इससे बैंकों के परिचालन दक्षता में सुधार आएगा और कारोबार भी बढ़ेगा जिससे अर्थव्यवस्था का भी विस्तार होगा। एकीकरण से विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में बैंकों की पहुंच बढ़ेगी और पूंजी का बेहतर उपयोग हो सकेगा।

एकीकरण की प्रक्रिया के तहत शिकायत निपटान प्रणाली बनाई जाएगी और सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। अगर शेयरधारकों को शेयरों की अदला-बदली अनुपात को लेकर कोई समस्या हो, जैसे कि उन्हें लगता हो कि पर्याप्त समय नहीं दिया गया या उन्हें और जानकारी की जरूरत है तो इस मंच पर वे अपने मसले को रख सकते हैं। बैंकों के निदेशक मंडल ने शेयरों की अदला-बदली अनुपात को मंजूरी दी है।

विलय प्रक्रिया में शामिल एक बैंक के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'शिकायतें मिलने के बाद समिति, जरूरत पड़ने पर सात दिन में बदलाव करने की सिफारिश कर सकती है, जो शेयरों की अदला-बदली का अंतिम अनुपात होगा।'

चंदा कोछड़ की याचिका खारिज

सुब्रत पांडा
मुंबई, 5 मार्च

- अपनी बर्खास्तगी को दी थी चुनौती
- पिछले साल बैंक ने किया था बर्खास्त
- न्यायालय ने मानी बैंक की दलील

बंबई उच्च न्यायालय ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी चंदा कोछड़ की इस निजी बैंक के खिलाफ दायर रिट याचिका आज खारिज कर दी। बैंक ने पिछले साल उन्हें बर्खास्त कर दिया था और उन्हें दिया गया बोनस वापस लेने का फैसला किया था। चंदा ने इसे अदालत में चुनौती दी थी।

न्यायालय ने बैंक की इस दलील को मान लिया कि चंदा की रिट याचिका सुनवाई के लायक नहीं है। आईसीआईसीआई ने कहा कि वह एक निजी बैंकिंग कंपनी है और रिट याचिका में विशुद्ध रूप से निजी आनुबंधिक शर्तों को चुनौती दी गई है। बैंक ने कहा कि इस याचिका का कोई कानूनी आधार नहीं है।

चंदा ने याचिका में उनकी बर्खास्तगी को अवैध करार देने, समय से पहले सेवानिवृत्ति के लिए उन्हें मिले लाभ और पारितोषिक की वसूली से परहेज करने और स्टॉक ऑप्शंस का इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी थी। बैंक ने कहा कि इनमें से कोई भी राहत वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। बैंक ने साथ ही कहा था कि चंदा ने अपनी याचिका में जो राहत मांगी थीं, वे विशुद्ध रूप से निजी चरित्र के थे।

चंदा का कहना था कि आईसीआईसीआई बैंक को उनकी सेवाएं समाप्त करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मंजूरी लेनी चाहिए थी। साथ ही उन्होंने अपनी बर्खास्तगी को मंजूरी देने के आरबीआई के फैसले को भी चुनौती दी थी। उनका कहना था कि यह कदम था और इसका कोई कानूनी आधार नहीं था। आईसीआईसीआई बैंक ने 31 जनवरी, 2019 को चंदा को बर्खास्त किया था जिसे केंद्रीय बैंक ने 13 मार्च को मंजूरी दी थी।

चंदा ने अपनी याचिका में कहा था कि आरबीआई ने दिमाग लगाए बिना आईसीआईसीआई के फैसले पर मुहर लगाई थी। यह बैंकिंग नियमन कानून की धारा 35बी (1)(बी) के प्रावधानों के खिलाफ है। बैंकिंग नियमन कानून के मुताबिक किसी बैंक के चेयरमैन या प्रबंध निदेशक के अनुबंध को खत्म करने के लिए आरबीआई की पूर्व अनुमति जरूरी है। उन्होंने कहा कि आरबीआई की पूर्व अनुमति अनिवार्य है और बर्खास्तगी के बाद मंजूरी नहीं ली जा सकती है। इस मामले में ऐसा नहीं किया गया और यह नियमों का उल्लंघन है।

आईसीआईसीआई बैंक ने अपने जवाब में कहा था कि 1949 के बैंकिंग नियमन कानून की धारा 35बी एक नियामकीय प्रावधान है। चंदा इसी प्रावधान के तहत अपनी बर्खास्तगी को रद्द करने की मांग कर रही थीं। बैंक ने साथ ही कहा कि चंदा इस बात से वाकिफ थीं कि धारा 35बी आरबीआई की नियामकीय और निगरानी शक्तियों का हिस्सा है और यह उन्हें कोई अधिकार या संरक्षण नहीं देता है। इसमें बैंक के कर्तव्यों की बात नहीं है बल्कि यह बैंकिंग कंपनी और उसके जमाकर्ताओं के संरक्षण से संबंधित है।

सभी प्राथमिक स्कूल बंद होली कार्यक्रम पर असर

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 5 मार्च

- दिल्ली सरकार के कार्यालयों में बायोमेट्रिक से हाजिरी में छूट
- कारोबारी संगठनों ने होली मिलन कार्यक्रम रद्द करने शुरू किए

कोरोनावायरस की वजह से दिल्ली के कारोबारी संगठनों से होली मिलन कार्यक्रम रद्द करने शुरू कर दिए हैं। विशेषज्ञ कोरोनावायरस रोकने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित होने के कार्यक्रमों से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। इस बीच, दिल्ली सरकार ने एहतियातन सभी प्राथमिक स्कूल 31 मार्च तक बंद करने के साथ ही सभी विभागों को कर्मचारियों की बायोमेट्रिक हाजिरी स्थगित करने की सलाह दी है।

गाजियाबाद में कोरोना वायरस का एक और मामला सामने आने के बाद देश में इससे संक्रमित लोगों की कुल संख्या 30 हो गई है।

कारोबारियों के मुताबिक दिल्ली में 100 से अधिक बड़े कारोबारी संगठन और 200 से 300 छोटे व स्थानीय बाजारों के कारोबारी संगठन हर साल होली मिलन समारोह आयोजित करते हैं। बड़े कारोबारी संगठनों के होली मिलन कार्यक्रमों का बजट 5 से 10 लाख रुपये और छोटों का 50 हजार से दो लाख रुपये होता है। कारोबारी संगठनों के होली मिलन समारोह का कुल बजट 10 से 15 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोनावायरस की वजह से अपने होली मिलन कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं।

ऑपरेटरों ने की सीएजी ऑडिट की मांग

सुरजीत दास गुप्ता
नई दिल्ली, 5 मार्च

दूरसंचार ऑपरेटरों ने दूरसंचार विभाग से अनुरोध किया है कि लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) के बकाये का सटीक आकलन के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) से उनके खातों की जांच कराई जाए। ऑपरेटरों का कहना है कि सीएजी के आकलन से उनके बकाये को लेकर अंतिम समाधान हो सकता है।

सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफऊ इंडिया के महानिदेशक राजन मैथ्यू ने कहा, 'हमने दूरसंचार विभाग से ऑपरेटरों पर बकाया राशि को अंतिम रूप देने का अनुरोध किया है ताकि इस मसले पर लंबी बहस न हो। इसका मतलब है कि सीएजी के द्वारा उनकी ऑडिट कराई जाए। वर्तमान में हमारे खातों की सीएजी जांच लंबित है, ऐसे में वह इसकी भी जांच कर सकता है। दूरसंचार कंपनियां नहीं चाहतीं कि कुछ साल बाद फिर कोई नई मांग का मामला सामने आए।'

एजीआर बकाये का गणित

कंपनी	विभाग के मुताबिक कुल बकाया	भुगतान	शेष बकाया
भारती/टेलीनॉर+	37,740	18,000	19,740
टाटा	13,823	4,197	9,626
वोडा-आइडिया	53,038	3,500	49,538
रिलायंस जियो	60	195	–

नोट : सभी आंकड़े करोड़ रुपये में, स्रोत : सीओएआई, उद्योग

यह मांग इसलिए भी तार्किक लगता है क्योंकि दूरसंचार विभाग की मांग और ऑपरेटरों द्वारा स्व-आकलन के आधार पर किए जा रहे भुगतान में काफी अंतर है। मौजूदा आंकड़ों के आधार पर कंपनियों ने कुल सकल समायोजित राजस्व की बकाया राशि में से 25,892 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, जो अदालत में की गई मांग 1,46,336 करोड़ रुपये का महज 17.6 फीसदी है। भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, टाटा टेली और रिलायंस जियो ने ही अब तक कुल या आंशिक राशि का भुगतान किया है। हालांकि उन्होंने अपने कुल बकाया का करीब 18 फीसदी का ही भुगतान किया है।

दूरसंचार कंपनियां लाइसेंस समझौते के एक प्रावधान का भी उल्लेख कर रही हैं जिसके तहत जुर्माने का भुगतान केवल लाइसेंस शुल्क के लिए ही किया जाएगा, वह भी तब जब भुगतान योग्य लाइसेंस शुल्क का 10 फीसदी से अधिक हो। कंपनियां इसी आधार पर बकाये की गणना कर रही हैं और इस मामले को टीडीसैट में ले जा सकती हैं।

ऑपरेटरों का कहना है कि हर साल उनकी ओर से किया गया भुगतान और आकलन एवं सत्यापन के बाद दूरसंचार विभाग द्वारा की गई मांग में अंतर 10 फीसदी से भी कम है। ऐसे में उन्हें केवल उस अंतर और उक्त राशि पर ब्याज का भुगतान करना है। उस राशि पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता।

दूरसंचार विभाग की मांग और कंपनियों द्वारा किए गए भुगतान में भारी अंतर के बारे में मैथ्यू ने कहा, 'सभी दूरसंचार कंपनियों ने अपनी गणना के हिसाब से लाइसेंस शुल्क और एसयूसी का भुगतान किया है और दूरसंचार विभाग के आकलन को लेकर विभिन्न कानूनी मंचों पर आपत्ति जताई है।' मैथ्यू ने कहा कि जुर्माने की वजह से ही दूरसंचार विभाग की मांग और कंपनियों की ओर से किए गए भुगतान में अंतर दिख रहा है।

खबरों में रहे स्टॉक

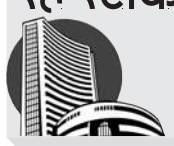

येस बैंक

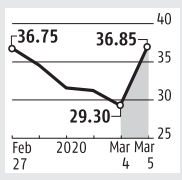

एसबीआई की अगुआई वाले कंसोर्टियम को बैंक का हिस्सा लेने की मंजूरी

₹ 29.30 पिछला बंद भाव
₹ 36.85 आज का बंद भाव
▲ 25.77 %

रिलायंस इंडस्ट्रीज

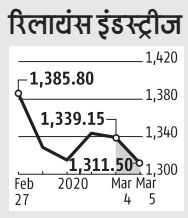

एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स में सबसे ज्यादा टूटने वाला शेयर

₹ 1,339.15 पिछला बंद भाव
₹ 1,311.25 आज का बंद भाव
▼ 2.06 %

महिंद्रा ऐंड महिंद्रा

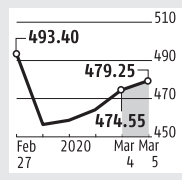

अप्रैल में भी आपूर्ति में अवरोध बने रहने की आशंका

₹ 474.55 पिछला बंद भाव
₹ 479.25 आज का बंद भाव
▲ 0.99 %

वी-मार्ट रिटेल

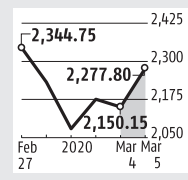

संभावनाओं में सुधार से बेहतर मूल्यांकन में मिलेगी मदद

₹ 2,150.15 पिछला बंद भाव
₹ 2,277.80 आज का बंद भाव
▲ 5.94 %

ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

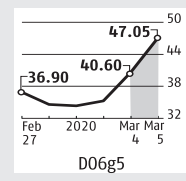

10 पीएसयू बैंकों का एकीकरण चार में करने की योजना को मिली मंजूरी

₹ 40.60 पिछला बंद भाव
₹ 47.05 आज का बंद भाव
▲ 15.89 %

संक्षेप में

सीजी पावर के खातों की जांच की याचिका मंजूर

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने गुरुवार को सीजी पावर ऐंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस के मामले में सरकार की अर्जी मंजूर करते हुए उसे कंपनी के 2014-15 से 2018-19 के दौर के खातों की जांच दोबारा करने की अनुमति दे दी। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने एनसीएलटी से आवेदन देकर यह जांच एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक से कराने की अनुमति मांगी थी ताकि जनहित में सच्चाई सामने लाई जा सके। एनसीएलटी के मुंबई पीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा कि सरकार वैश एसोसिएट्स की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करे और अलग से जांच कराए। न्यायाधिकरण के सदस्य भास्कर पंतुला मोहन और राजेश शर्मा के पीठ ने सीजी पावर ऐंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस के संस्थापक गौतम थापर की अपने आदेश पर रोक के आग्रह वाली अर्जी खारिज कर दी। इससे पहले, जनवरी में एनसीएलटी ने वैश एसोसिएट्स द्वारा जमा की गई रिपोर्ट खारिज करते हुए उसे फर्जी बताया था। *भाषा*

दूरसंचार कंपनियों ने दिया सुझाव

मोबाइल डेटा की तय हो न्यूनतम कीमत

मेघा मनचंदा
नई दिल्ली, 5 मार्च

भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो जैसी प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों ने मोबाइल डेटा सेवाओं के लिए न्यूनतम निर्धारित मूल्य तय किए जाने की मांग की है और कहा है कि वॉइस कॉल दरें बाजार के लिए छोड़ी जानी चाहिए।

इन कंपनियों ने कहा है कि डेटा कीमतों का नियमन क्षेत्र की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

एयरटेल ने कहा है, 'हमारा मानना है कि मोबाइल डेटा सेवाओं के लिए फ्लोर प्राइस (न्यूनतम निर्धारित कीमत) तय की जानी चाहिए। यह जरूरी है कि न्यूनतम कीमत टैरिफ प्लांस (यानी रिटेल कंज्यूमर, कॉरपोरेट आदि) की सभी श्रेणियों के लिए लागू होनी चाहिए।'

भारती एयरटेल ने डेटा सेवाओं के लिए न्यूनतम कीमत तीन संभावित तरीकों के साथ दो वर्षों के लिए तय किए जाने का सुझाव दिया है।

पहले तरीके में, एक महीने में 1जीबी डेटा के साथ वॉइस अनलिमिटेड की पेशकश के लिए न्यूनतम कीमत 165 रुपये (75 रुपये- न्यूनतम सदस्यता शुल्क, 60 रुपये- अनलिमिटेड वॉइस और 30 रुपये 1जीबी डेटा के लिए) तय की जा सकती है।

दूसरे तरीके में, 5जीबी का पहला डेटा ब्लॉक 30 रुपये पर निर्धारित होगा और उसके बाद के ब्लॉक 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये पर। यह प्रति जीबी कीमत मौजूदा खपत और 10 प्रतिशत के आरओसीई के आधार पर 22 रुपये पर अनुमानित है।

तीसरे तरीके में, इस्तेमाल के लिए रोजाना जीबी पैक को तैयार किए जाने का सुझाव दिया गया है, महीने के लिए शुरुआती प्रति जीबी पैक (1जीबी प्रतिदिन) 219 रुपये से 349 रुपये है। प्रति जीबी कीमत 10 प्रतिशत के आरओसीई के आधार पर 22 रुपये पर अनुमानित है।

रिलायंस जियो ने कहा है कि दरें बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि इससे इस्तेमाल में बड़ी कमी आ सकती है। मौजूदा समय में ये बढ़ाकर 15 रुपये प्रति जीबी की जा सकती हैं और डेटा खपत के आधार पर 6-9 महीने के बाद 20 रुपये प्रति जीबी की जा सकती हैं। जियो ने कहा है कि ट्राई तीन साल बाद अपने दर आदेश की समीक्षा कर सकता है।

जहां वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो ने इंटरकनेक्शन इस्तेमाल शुल्क लागू होने की स्थिति में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा फ्री ऑफ-नेट कॉल की पेशकश पर प्रतिबंध की वकालत की है, वहीं भारती एयरटेल ने इसका विरोध किया है।

दूरसंचार कंपनियों का कहना है कि इस्तेमाल वॉइस सेवा अतीत में दूरसंचार राजस्व का प्रमुख स्रोत रही है। हालांकि अब कुल राजस्व में इसका योगदान काफी घटा है। इसके अलावा, नई प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल से भी वॉइस को डेटा के तौर पर इसतेमाल किया जा रहा है। इसे देखते हुए दूरसंचार कंपनियों के लिए डेटा प्रमुख राजस्व स्रोत बन गया है।

एयरटेल ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है, 'हमने वॉइस के लिए कोई खास न्यूनतम कीमत का प्रस्ताव नहीं रखा है और वॉइस की कीमत से परहेज बनाए रखा जा सकता है।'

- भारती एयरटेल ने डेटा सेवाओं के लिए न्यूनतम कीमत दो वर्षों के लिए तय किए जाने का सुझाव दिया है
- दूरसंचार कंपनियों का कहना है कि मौजूदा समय में कुल राजस्व में वॉइस सेवा खंड का योगदान काफी घटा है

नॉन-सिरोटिक लीवर के लिए जाइडस ने बनाई पहली दवा

विनय उमरजी
अहमदाबाद, 5 मार्च

दवा कंपनी कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड (जाइडस कैडिला) ने एक ऐसी दवा विकसित की है, जिससे शराब से इतर वजहों से होने वाली यकृत (लीवर) की गंभीर बीमारी ठीक हो सकेगी। इससे यकृत के प्रत्यारोपण की जरूरत नहीं पड़ सकती है। कंपनी ने नॉन-सिरोटिक नॉन एल्कोहलिक स्टीयटोहेपेटाइटिस (नैस) के इलाज के लिए पहली दवा की घोषणा की है। कंपनी की दवा- सारोग्लिटजर के लिए नए दवा आवदेन को भारतीय दवा महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने मंजूरी दे दी है। इससे दवा की व्यावसायिक बिक्री शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शारविल पटेल के मुताबिक सारोग्लिटजर की व्यावसायिक बिक्री शुरू करने में तीन महीने से अधिक समय नहीं लगेगा।

उन्होंने कहा कि कंपनी ने शुरुआत मेमं यह दवा महानगरों और टीयर-1 बाजारों में पेश करने की योजना बनाई है। इस दवा को मैक्सिकों में भी मंजूरी मिल गई है, इसलिए यह वहां भी जल्द ही शुरू की जा सकती है। वहीं अमेरिकी बाजार में दवा को पेश करने में कुछ समय लग सकता है। पश्चिम एशिया और लैटिन अमेरिका समेत भारत में शराब से इतर फैटी लीवर की बीमारी से पीड़ित 30 फीसदी आबादी है। इस बीमारी से बाद में सेल्यूलर स्तर पर इन्फलामेशन पैदा हो जाता है, जिसे नैस कहा जाता है। नैस यकृत की लगातार बढ़ने वाली बीमारी है। यह लीवर पर फैट जमा होने के साथ शुरुआत होती है। यह सिरोसिस और लीवर फेल होने का कारण बन सकती है। इस समय 'नैस' के इलाज के लिए विश्व में कोई स्वीकृत दवा नहीं है। यह बीमारी बड़े स्तर पर है, जिससे दुनियाभर में 10 से 30 फीसदी आबादी प्रभावित है।

जाइडस समूह के चेयरमैन पंकज पटेल ने कहा, 'हम इस बात से खुश हैं कि 'नैस' बीमारी वाले मरीजों के लिए एक नई खोजने और विकसित करने के हमारे प्रयास सफल रहे हैं। सारोग्लिटजर नई उम्मीद मुहैया कराए कराएगी और भारत में नैस से पीड़ित लाखों लोगों को नया जीवन देगी।'

भारत की करीब 25 फीसदी आबादी में 'नैस' से पीड़ित होने का अनुमान है। हेपेटाइटिस सी और शराब से संबंधित यकृत की बीमारियों के बाद 'नैस' सिरोसिस का एक प्रमुख कारण है। एडवांस्ड सिरोसिस या लीवर फेल होने की स्थिति में केवल लीवर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र विकल्प बचता है।

आरकॉम के लिए समाधान योजना को मिली मंजूरी

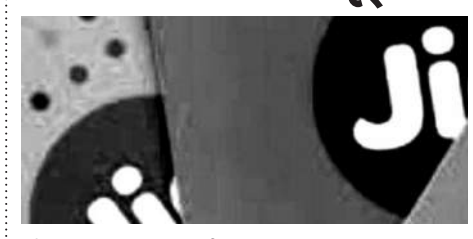

बीएस संवाददाता/एजेंसियां
नई दिल्ली, 5 मार्च

रिलायंस कम्युनिकेशंस के लिए 23,000 करोड़ रुपये की समाधान योजना को ऋणदाताओं द्वारा मंजूरी दिए जाने से लगभग 5,500 करोड़ रुपये की पूंजी चीन के बैंकों को मिलेगी। इससे उनके मूल बकाया का लगभग 55 प्रतिशत हिस्सा मिल जाएगा, जिनमें वे ऋणदाता भी शामिल हैं जिनके लिए कंपनी के प्रवर्तक अनिल अंबानी द्वारा कथित तौर पर व्यक्तिगत गारंटी दी गई थी। नियामक को भेजी जानकारी में आरकॉम ने कहा है, '4 मार्च 2020 को समाप्त हुई ई-वोटिंग में आरकॉम के लेनदारों की समिति 100 प्रतिशत वोटिंग के जरिये यूवी ऐसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड द्वारा सौंपी गई कर्ज समाधान योजना को मंजूरी प्रदान की थी।'

कंपनी ने कहा है, 'आरकॉम की सहायक इकाइयों (रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और रिलायंस इन्फ्राटेल, जो कॉरपोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया से गुजर रही हैं) को ध्यान में रखते हुए यूवी ऐसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड द्वारा अपनी इकाई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जरिये सौंपी गई समाधान योजनाएं उपर्युक्त कंपनियों की सीओसी द्वारा 100 प्रतिशत मतदान के साथ स्वीकृत की गई थीं।' हालांकि इसमें स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया था और कहा गया कि योजनाएं अंतिम मंजूरी के लिए एनसीएलटी के मुंबई पीठ को सौंपी जाएंगी। इसमें कहा गया है कि जहां रिलायंस जियो को 4,700 करोड़ रुपये के लिए रिलायंस इन्फ्राटेल की टावर और फाइबर परिसंपत्तियां मिलेंगी, वहीं यूवी ऐसेट रीकंस्ट्रक्शन (यूवीएआरसी) को आरकॉम और रिलायंस टेलीकॉम (स्पेक्ट्रम) की 14,000 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियां मिलेंगी। क्लाबैक क्लॉज की वजह से समाधान योजना के तहत 23,000 करोड़ रुपये मिलेंगे जो चीन के बैंकों का बकाया चुकाने में खर्च किए जाएंगे, जो सबसे बड़े ऋणदाता हैं। चीन के बैंकों को 5,500 करोड़ रुपये मिलेंगे और उनका मूल कर्ज घटकर 4,500 करोड़ रुपये रह जाएगा। चीन के बैंकों - इंडस्ट्रियल ऐंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड, चाइना डेवलपमेंट बैंक और एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ चाइना ने बकाया वसूलने के लिए अंबानी को ब्रिटिश अदालत में चुनौती दी थी।

वहीं भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में बुधवार को सीओसी ने आरकॉम और उसकी दो सहायक इकाइयों की बिक्री और रिलायंस जियो को टावर परिसंत्तियों की बिक्री से संबंधित समिति के समाधान के पक्ष में मतदान किया। इस कदम के साथ जियो और कनाडाई पीई फंड ब्रुकफील्ड जियो की प्रमुख पट्टेदार के तौर पर संयुक्त रूप से देश की सबसे बड़ी टावर ऑपरेटर होंगी। इस सौदे के बाद जियो-ब्रुकफील्ड की जोड़ी का 175,000 से अधिक टावरों पर नियंत्रण हो जाएगा जो प्रस्तावित इकाई के 165,000 टावरों की संख्या में अधिक है। इससे जियो को अपनी फाइबर क्षमता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी, जो इस सौदे के बाद मौजूदा 450,000 किलोमीटर से बढ़कर 600,000 किलोमीटर हो जाएगी।

एस्सार समूह फिर शुरू करेगा निवेश : रुइया

देव चटर्जी
मुंबई, 5 मार्च

एस्सार समूह भारत व विदेश में फिर से निवेश शुरू करने की योजना बना रहा है और इस तरह से समूह के प्रवर्तक फिर से कारोबार में लौटने की कोशिश में हैं।

निवेशकों और मीडिया को लिखे पत्र में कंपनी प्रवर्तकों ने कहा है कि समूह अभी सालाना करीब 1 लाख करोड़ रुपये की आय अर्जित कर रहा है और यह मुख्य रूप से ब्रिटेन की रिफाइनरी से आ रहा है।

शशि, रवि और प्रशांत रुइया ने कहा, हल्की बैलेंस शीट के साथ एस्सार अपने मौजूदा पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाने के साथ अब बढ़त के नए चरण की ओर जाने के लिए तैयार है। एस्सार अपने उद्यम कौशल, विशाल मानव संसाधन और दशकों के अनुभव व नवोन्मेष का इस्तेमाल नए मौकों में करने और सभी हितधारकों के लिए कीमत सृजन में जारी रखेगा।

कुछ साल पहले समूह ने वैश्विक व देसी आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए और स्टील व बिजली कारोबार में नियामकीय अवरोध के कारण कर्ज घटाने का फैसला लिया था। पत्र में कहा गया है, एस्सार स्टील कॉम्पलेक्स के लिए गैस आपूर्ति का अनुबंध 2012 में वापस ले लिया गया और बिजली संयंत्रों को आवंटित कोयला खदान साल 2014 में रद्द कर दिया गया, जिससे कुछ प्रमुख परिचालित परिसंपत्तियां आंशिक तौर पर बंद हो गईं। हमने इन चुनौतियों का सामना किया और फैसला लिया कि उधारी में काफी ज्यादा कमी लाना बुद्धिमानी होगी।

समूह ने पिछले तीन वर्षों में बैंकों का करीब 1.40 लाख करोड़ रुपये कर्ज चुकाया। प्रवर्तकों ने कहा, एस्सार की तरफ से खड़ी गई परिसंपत्तियों ने 40 अरब डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया, जो उम्दा व विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाली हमारी परिसंपत्तियों में प्रतिबिंबित हुई है। एस्सार-रोसनेफ्ट सौदे से 86,000 करोड़ रुपये से ज्यादा एफडीआई मिली।

पिछले साल कंपनी 1 करोड़ टन सालाना क्षमता वाला स्टील कॉम्पलेक्स आर्सेलरमित्तल के हाथों गंवा दिया जब बैंकों ने कंपनी को कर्ज भुगतान में चूक के बाद एनसीएलटी में घसीट लिया। समूह के पास अभी बंदरगाह, खदान और जहाजरानी के अलावा देश व विदेश में बिजली परियोजनाएं हैं।

निवेश की हो रही तैयारी

- समूह के प्रवर्तकों ने निवेशकों और मीडिया को लिखा पत्र
- प्रवर्तकों ने कहा है, हल्की बैलेंस शीट के साथ नए चरण की ओर बढ़ने के लिए तैयार है समूह

जिंस डेरिवेटिव में दांव लगाने के लिए कमर कस रहे म्युचुअल फंड

इससे संबंधित नई योजना शुरू करेंगे, नई नियुक्तियां भी होंगी

जश कृपलानी
मुंबई, 5 मार्च

म्युचुअल फंड कंपनियां अपनी क्षमता की समीक्षा कर रही है क्योंकि बाजार नियामक सेबी की तरफ से कमोडिटी डेरिवेटिव बाजार 27 लाख करोड़ रुपये वाले म्युचुअल फंड उद्योग के लिए खोले जाने के बाद वे जिंस से जुड़ाव रखने वाली योजनाओं का प्रबंधन शुरू करेंगी।

टाटा एमएफ के प्रमुख (जिंस रणनीति) ए. ज्ञान ने कहा, हम और विश्लेषकों व फंड मैनेजरों की नियुक्ति करेंगे क्योंकि उपलब्ध जिंसों का बास्केट काफी बड़ा है। इस मामले में सेबी की मंजूरी मिल गई है।

फंड हाउस ने हाल में टाटा मल्टी ऐसेट ऑपरच्युनिटीज फंड पेश किया है, जो कमोडिटी डेरिवेटिव में 10 से 25 फीसदी निवेश कर सकता है।

उद्योग के सूत्रों के मुताबिक, कुछ फंड हाउस वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) की योजना बना रहे हैं, जो कमोडिटी डेरिवेटिव में निवेश कर सकता है। पिछले साल बाजार नियामक सेबी ने म्युचुअल फंडों को एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव (संवेदनशील जिंसों को छोड़कर) में भागीदारी की अनुमति दी थी। इससे ट्रेड के लिए म्युचुअल फंडों की पहुंच 20-25 जिंसों तक हो गई।

निप्पॉन लाइफ इंडिया एमएफ एक अन्य फंड हाउस है जो कमोडिटी डेरिवेटिव से जुड़ाव रखने वाला प्रॉडक्ट पोर्टफोलियो बनाने पर विचार कर रहा है।

निप्पॉन लाइफ इंडिया एमएफ के कार्यकारी निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी संदीप सिक्का ने कहा, पोर्टफोलियो को विशाखित करने के अलावा जिंस बाजार विभिन्न जिंसों में मध्यम से लंबी अवधि के लिए निवेश का मौका देता है। हमारा इरादा वैसी योजनाएं पेश करने का है जो निवेशकों के ऐसे मौकों में भागीदारी का अवसर दे

उन्होंने कहा, कमोडिटी आर्बिट्रेज दिलचस्प क्षेत्र है जो तब उभरेगा जब हम आगे बढ़ेंगे। हम अपनी टीम में इजाफा करेंगे। फंड हाउस ने मल्टी ऐसेट फंड के लिए आवेदन किया है, जो अपने फंड का 10 से 30 फीसदी कमोडिटी डेरिवेटिव में आवंटित कर सकता है।

अन्य कंपनियों में एडलवाइस एमएफ और पीजीआईएम इंडिया एमएफ भी कमोडिटी से जुड़ाव वाली योजनाएं पेश करने पर विचार कर रही हैं। पीजीआईएम इंडिया एमएफ के सीईओ अजित मेनन ने कहा, यह विशाखन का मौका देता है ताकि निवेशकों को उतारचढ़ाव से निपटने में मदद मिले। हम ऐसी पेशकश की संभावना तलाश रहे हैं, लेकिन इसके लिए सही विशेषज्ञता महत्वपूर्ण है।

एडलवाइस एमएफ की सीईओ राधिका गुप्ता ने कहा, हम मौके का आकलन कर रहे हैं और ऐसे फंड की पेशकश के लिए सही वक्त का इंतजार करेंगे। उद्योग के भागीदारों ने कहा कि वैश्विक स्तर पर म्युचुअल फंडों के लिए जिंस लोकप्रिय निवेश के तौर पर उभरा है। एक अनुमान के मुताबिक, दुनिया भर में विभिन्न फंड हाउस ने करीब 1 लाख करोड़ डॉलर का निवेश किया है।

जिंस डेरिवेटिव

- पिछले साल बाजार नियामक सेबी ने म्युचुअल फंडों को एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव (संवेदनशील जिंसों को छोड़कर) में भागीदारी की अनुमति दी थी
- इससे ट्रेड के लिए म्युचुअल फंडों की पहुंच 20-25 जिंसों तक हो गई

संक्षेप में

ई-वोटिंग प्रक्रिया में सुधार पर विचार कर रहा सेबी

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने गुरुवार को ई-वोटिंग प्रक्रिया में सुधार का प्रस्ताव किया, जिसका इस्तेमाल शेयरधारक सूचीबद्ध कंपनियों की तरफ से पेश प्रस्ताव की मंजूरी में करते हैं। अभी यह सेवा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता मुहैया कराते हैं। इस प्रक्रिया में अलग-अलग ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के साथ शेयरधारकों का पंजीकरण और अलग-अलग यूजर आईडी व पासवर्ड आदि जुड़ा होता है। बाजार नियामक ने मल्टीपल लॉगइन को छोड़ने और वेब आधारित सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रखा है, जो कई ई-वोटिंग सेवा प्रदाता तक पहुंच में सक्षम बनाएगा। नियामक ने इस महीने के आखिर तक सार्वजनिक टिप्पणी आमंत्रित की है। *बीएस*

रिलायंस रिटेल ने किया एसकेडीएस का अधिग्रहण

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) की सहायक रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (आरआरवीएल) ने 152.5 करोड़ रुपये में श्री कन्नन डिपार्टमेंटल स्टोर प्राइवेट लिमिटेड (एसकेडीएस) का अधिग्रहण किया है। आरआरवीएल 7,86,191 इक्विटी शेयर खरीदेगी, जो एसकेडीएस की 100 फीसदी इक्विटी शेयर पूंजी है। एसकेडीएस 15 सितंबर 1999 को बनी थी। यह कंपनी फल-सब्जियों, डेयरी उत्पादों, खाद्य पदार्थों, होम एवं पर्सनल केयर और सामान्य वस्तुओं की खुदरा बिक्री करती है। इस समय एसकेडीएस कोयंबत्तूर और उसके आसपास के क्षेत्रों में 29 स्टोरों का परिचालन करती है। *बीएस*

कैम्स की हिस्सेदारी के विनिवेश की योजना सौंपे एनएसई : सेबी

नैशनल स्टॉक एक्सचेंज को कैम्स की पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए मिल सकता है और समय

समी मोडक
मुंबई, 5 मार्च

नैशनल स्टॉक एक्सचेंज को कंप्यूटर ऐज मैनेजमेंट सर्विसेज (कैम्स) की 37 फीसदी हिस्सेदारी के विनिवेश में कुछ राहत मिल सकती है। पिछले महीने बाजार नियामक सेबी ने एनसएसई को रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट की पूरी हिस्सेदारी एक साल के भीतर बेचने का निर्देश दिया था। इस आदेश ने एक्सचेंज को असमंजस में डाल दिया क्योंकि कैम्स ने पिछले महीने ही आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के लिए आवेदन किया है।

आईपीओ के जरिये एनएसई 12.5 फीसदी हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रहा है। आईपीओ से एनएसई को अपनी एक तिहाई हिस्सेदारी बेचने में मदद मिलेगी, बाकी 24.5 फीसदी हिस्सेदारी एक साल के लिए लॉक हो जाएगी।

सेबी के दिशानिर्देश के तहत आईपीओ पूर्व शेयरधारिता सूचीबद्धता से एक साल की अवधि तक नहीं बेची जा सकती। इसका मतलब यह हुआ कि एनएसई अपनी पूरी हिस्सेदारी फरवरी 2021 तक बेचने के सेबी के निर्देश का पालन नहीं कर पाएगा।

सूत्रों ने कहा कि आईपीओ का कामकाज संभाल रहे निवेश बैंकरों ने नियामक के सामने यह मसला उठाया है। सेबी ने इस पर राहत देने से शायद मना कर दिया है।

सेबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमने एक्सचेंज को हिस्सेदारी विनिवेश की योजना सौंपने को कहा है। हमें पता है कि आईपीओ के बाद हिस्सेदारी विनिवेश का मसला खड़ा हो सकता है। हम एनएसई की तरफ से प्रस्ताव सौंपने के बाद फैसला लेंगे।

सूत्रों ने कहा कि जिन प्रस्तावों पर चर्चा हुई है उनमें से एक आईपीओ ढांचे में बदलाव है। मौजूदा प्रस्ताव के तहत एनएसई व अन्य चार निवेशक कुल 25 फीसदी हिस्सा इस आईपीओ के जरिए बेच रहे हैं।

एक निवेश बैंकर ने कहा, अगर एनएसई को आईपीओ में पूरी हिस्सेदारी बेचनी हो तो उसे मौजूदा प्रस्ताव में अहम बदलाव करने होंगे। कुछ निवेशकों को अपनी विनिवेश योजना रद्द करनी पड़ सकती है।

आईपीओ में वारबर्ग पिनकस 8.5 फीसदी हिस्सेदारी, ए. इन्वेस्टमेंट्स व एचडीएफसी समूह 2-2 फीसदी हिस्सा बेच रहा है। बैंकर ने कहा, ज्यादा व्यावहारिक समाधान यह होगा कि आईपीओ अपनी योजना के मुताबिक आगे बढ़े और एनएसई शपथपत्र दे कि वह लॉक इन अवधि पूरा होने के बाद बाकी हिस्सेदारी बेच देगा। सेबी ने अभी कैम्स के पेशकश दस्तावेज को मंजूरी नहीं दी है, जो 9 जनवरी को जमा कराई गई थी।

- आईपीओ के जरिये एनएसई 12.5 फीसदी हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रहा है
- अगर एनएसई को आईपीओ में पूरी हिस्सेदारी बेचनी हो तो उसे मौजूदा प्रस्ताव में अहम बदलाव करने होंगे
- सेबी ने अभी कैम्स के पेशकश दस्तावेज को मंजूरी नहीं दी है, जो 9 जनवरी को जमा कराई गई थी

सीडीआर ढांचे से बाहर निकली जिंदल स्टेनलेस

अदिति दिवेकर
मुंबई, 5 मार्च

जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड ने आज ऐलान किया वह कंपनी कर्ज पुनर्गठन (सीडीआर) ढांचे से कामयाबी के साथ बाहर निकल गई है और यह 31 मार्च 2019 से प्रभावी हुआ। दिल्ली की कंपनी को बुधवार को इस बारे में सीडीआर लेनदारों के कंसोर्टियम से पत्र मिला। इसके मुताबिक मौजूदा सीडीआर लेनदारों को करीब 275 करोड़ रुपये नकद मिले हैं, जो उनकी मौजूदा वित्त वर्ष की आय में जुड़ेगी। इसके अतिरिक्त जिंदल स्टेनलेस ने बकाया परिवर्तनीय तरजीही शेयर की रिडीम कर दिया, जो जून 2017 में लेनदारों को जारी किए गए थे और करीब 558 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया। इस तरह से लेनदारों को करीब 833 करोड़ रुपये मिल गए।

इससे पहले प्रवर्तक समूह की इकाई ने इक्विटी झोंकी और इसके बाद जिंदल स्टेनलेस ने 400 करोड़ रुपये की एनसीडी कोटक स्पेशल सिचुएशन फंड को जारी किया। इन फंडों ने जेएसएल को परिवर्तनीय तरजीही शेयर का भुगतान करने में मदद की।

कोटक स्पेशल सिचुएशन फंड ने द्वितीयक बाजार के जरिये कंपनी की 5 फीसदी इक्विटी हिस्सेदारी ली, जो कंपनी के परिचालन व बढ़त के परिदृश्य पर निवेशकों का भरोसा बताता है।

कंपनी ने अपने कर्ज इक्विटी अनुपात में सुधार देखा है, जो 31 दिसंबर 2019 को 1.3 फीसदी रहा जबकि मार्च 2017 में यह 3.2 फीसदी रहा था।

एम्बेसी समूह से निकलना चाहती है वारबर्ग पिनकस

राघवेंद्र कामत
मुंबई, 5 मार्च

अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी फर्म वारबर्ग पिनकस एम्बेसी इंडस्ट्रियल पार्क्स से निकलना चाहती है, जो बेंगलूरु के एम्बेसी समूह के साथ उसका संयुक्त उद्यम है। साढ़े चार साल पहले कंपनी ने देश में इंडस्ट्रियल व वेयरहाउसिंग क्षेत्र में निर्माण के लिए 25 करोड़ डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

संयुक्त उद्यम को वारबर्ग से 17.5 करोड़ डॉलर की इक्विटी प्रतिबद्धता मिली हुई है, वहीं एम्बेसी ने 7.5 करोड़ डॉलर लगाए हैं। सूत्रों ने कहा, संयुक्त उद्यम में जिस गति से जमीन अधिग्रहण व प्रगति हुई है, उससे वारबर्ग पिनकस खुश नहीं है।

हालांकि सूत्रों ने कहा कि एम्बेसी के प्रवर्तक संयुक्त उद्यम में वारबर्ग पिनकस की हिस्सेदारी खरीद सकते हैं, लेकिन इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई। इस संबंध में वारबर्ग ने कोई टिप्पणी नहीं की। एम्बेसी के मुख्य परिचालन अधिकारी आदित्य विरमानी ने कहा, हमारा पोर्टफोलियो दूसरा सबसे बड़ा पोर्टफोलियो था और पूंजी लगाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं थी। उन्होंने कहा, हम सिर्फ जमीन के सौदे के मामले में संकीर्ण हैं क्योंकि इसी जगह मार्जिन हासिल होता है।

एम्बेसी के चेयरमैन जीतू विरमानी से संपर्क नहीं हो पाया। यह उद्यम पुणे, दिल्ली, एनसीआर, तमिलनाडु के श्रीपेरुंबदूर व होसूर के अलावा हैदराबाद में चरणबद्ध तरीके से इंडस्ट्रियल व वेयरहाउसिंग पार्क्स विकसित कर रहा है।

- संयुक्त उद्यम के तहत साल 2024 तक इंडस्ट्रियल व वेयरहाउस क्षेत्र में 3.5 करोड़ वर्गफुट विकसित करने की योजना है

पिछले साल अक्टूबर में दिए साक्षात्कार में आदित्य विरमानी ने कहा था कि साल 2016 से परिचालन शुरू होने के बाद से संयुक्त उद्यम ने 8 करोड़ डॉलर निवेश किया था और इन परियोजनाओं को पूरी करने के लिए 25-30 करोड़ डॉलर निवेश करेगा। उन्होंने कहा कि संयुक्त उद्यम ने 27 लाख वर्गफुट जगह विकसित किया है और 70 लाख वर्गफुट और विकसित करने की योजना है।

संयुक्त उद्यम के तहत साल 2024 तक इंडस्ट्रियल व वेयरहाउस क्षेत्र में 3.5 करोड़ वर्गफुट विकसित करने की योजना है। संयुक्त उद्यम के पहले सीईओ अंशुल सिंघल ने पिछले साल एम्बेसी इंडस्ट्रियल पार्क्स छोड़ने के बाद खुद का उद्यम स्थापित किया।

ई-कॉमर्स से बढ़ती मांग को देखते हुए पीई फर्मों और पेंशन फंडों मसलन सीपीपीआईबी, वारबर्ग पिनकस आदि ने पिछले पांच वर्षों में 5 अरब डॉलर से ज्यादा फंड की प्रतिबद्धता जताई है।

जेम पोर्टल पर रेल व रक्षा खरीद जल्द

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 5 मार्च

देश के दो सबसे बड़े सरकारी खरीदार रक्षा और रेलवे की सार्वजनिक खरीद को जल्द ही वाणिज्य विभाग के सरकारी ई-मार्केटप्लेस में शामिल कर लिया जाएगा। अधिकारियों ने आज कहा कि सितंबर तक भारतीय रेलवे ई-खरीद व्यवस्था (आईआरईपीएस), रक्षा ई-खरीद पोर्टल और केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल से खरीदी जाने वाली सभी सामान्य उपभोग की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद जेम के माध्यम से होगी।

सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम के मुताबिक आईआरईपीएस हर महीने 30,000 से ज्यादा टेंडर प्रकाशित करती है और उसके ऑनलाइन लेन देन का मूल्य 2019 के मध्य तक 10,600 करोड़ रुपये रहा है।

जेम के मुख्य कार्याधिकारी टल्लन कुमार ने कहा, 'एकीकृत खरीद व्यवस्था की योजना के तहत सभी पोर्टल जेम के तहत लाए जाएंगे। इससे खरीदार के साथ साथ हजारों की संख्या में वेंडरों के लिए ज्यादा स्पष्टता मिल सकेगी और बेहतर मूल्य की खोज में मदद मिलेगी।'

जेम के माध्यम से कुल संचयी खरीद करोड़ रु.	48,890
जेम पर ऑर्डर की कुल संख्या	36,06,889
उत्पादों व सेवाओं की पेशकश की कुल संख्या	20,91,674
पंजीकृत खरीदारों की कुल संख्या	43,880
विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं की कुल संख्या	3,42,455

कुल खरीद में हिस्सा

एमएससएमई विक्रेता **76.276**

महिला विक्रेता **10,144**

स्टार्ट अप विक्रेता **4,397**

स्रोतः सरकार का ई-मार्केटप्लेस

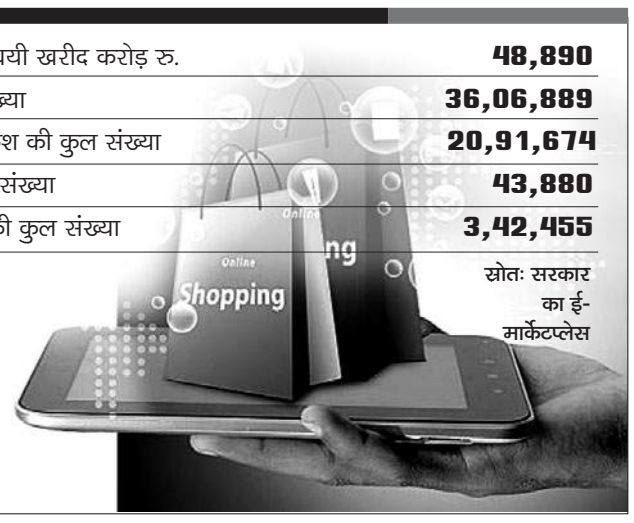

यह कदम देश में सरकारी खरीद के एक स्रोत रखने की रणनीति का हिस्सा है। मोदी सरकार की यह दीर्घावधि योजना भ्रष्टाचार कम करने, पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए है।

बहरहाल यह लक्ष्य अभी सरकार को हासिल करना है क्योंकि सरकार के विभागों ने जेम से इतर खरीद जारी रखी है। अक्टूबर 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने जेम व्यवस्था के बाहर 91,000 करोड़ रुपये की खरीद की है। एक सरकारी अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड से बातचीत में इस बात की पुष्टि की कि उसके बाद से खरीद बढ़ी है।

जेम के अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि सरकार के जनरल फाइनैंसिंग रूल (जीएफआर) 2017 में यह अनिवार्य किया गया है कि सभी सरकारी खरीद पोर्टल के माध्यम से होगी। आधिकारिक अनुमान के मुताबिक वाणिज्य विभाग ने 2019-20 में 50,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य दिखाया था, जिसे 2021 तक बढ़ाकर एक लाख करोड़ रुपये किया जाना था।

कुमार ने यह भी साफ किया कि जेम में हाल फिलहाल में निजी खरीदारों को शामिल नहीं किया जाएगा, जैसा कि पहले घोषित किया गया था। इस कदम के तहत सरकार के पोर्टल को सीधे दिग्गज ई-कारोबारियों से प्रतिस्पर्धा करने की योजना है। कुमार ने कहा कि ऐसा बाद में किया जा सकता है।

सरकार जल्द ही खरीदारों व विक्रेताओं के लिए गैर मौद्रिक प्रोत्साहन मुहैया कराएगी। साथ ही समय पर भुगतान, विक्रेता को संदर्भित करने और सूची में संशोधन आदि पर पुरस्कार दिया जाएगा। इन पुरस्कारों का इस्तेमाल तेज मंजूरियों व सहायता डेस्क में प्राथमिकता के लिए किया जा सकेगा।

इसे छोटी फर्मों को लुभाने के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार ने एमएसएमई पर मौजूद जेम के लिए ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) के तहत कर्ज की सुविदा की पेशकश शुरू की है। यह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक समर्थित बिल छूट सेवा है, जो उत्पाद भेजने के पहले और बाद में मिलती है।

वहीं दूसरी तरफ छोटे कारोबारी लगातार शिकायत कर रहे हैं कि सरकारी निकायों द्वारा उनके माल के भुगतान में बहुत देरी की जा रही है। जेम ने इसके लिए जेम पूल अकाउंट पर जोर दिया है, जहां राज्य अपनी खरीद के लिए अग्रिम भुगतान कर सकते हैं, लेकिन उससे निकासी नहीं कर सकते हैं, जिससे धन की गैर उपलब्धता की स्थिति खत्म की जा सके।

कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज 7 साल के निचले स्तर पर पहुंचा

बीएस संवाददाता/एजेंसियां
नई दिल्ली, 5 मार्च

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने आज चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर घटाकर 8.5 प्रतिशत करने की घोषणा की है। यह इसका सात साल का न्यूनतम स्तर है।

ईपीएफओ ने पिछले वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर 8.65 प्रतिशत का ब्याज दिया था। ईपीएफओ में मोटे तौर पर 17 करोड़ कर्मचारी धन जमा करते हैं। ईपीएफओ के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक में यह फैसला किया गया।

श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बैठक के बाद कहा, 'ईपीएफओ ने सीबीटी की आज हुई बैठक में 2019-20 के लिए भविष्य निधि जमा पर 8.5 प्रतिशत ब्याज देने का निर्णय किया है।' मंत्री ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.5 प्रतिशत ब्याज देने से ईपीएफओ के पास 700 करोड़ रुपये का अधिशेष होगा। मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा, 'ईपीएफओ अगर 8.55 प्रतिशत ब्याज देता तो उसके पास 300 करोड़ रुपए का अधिशेष रहता। इससे ज्यादा ब्याज देने पर ईपीएफओ को नुकसान होता।'

17 करोड़ कर्मियों पर पड़ेगा असर

बचत के साधन	ब्याज दर
ईपीएफ	8.5*
पीपीएफ	7.9
5 साल सावधि जमा	7.7
राष्ट्रीय बचत पत्र	7.9
जीपीएफ	7.9
बचत खाता जमा	4.0

*अधिसूचित होना बाकी, 2019-20 के लिए प्रस्तावित
स्रोतः ईपीएफओ, वित्त मंत्रालय

ईपीएफ जमा पर 2019-20 के लिए घोषित ब्याज दर 2012-13 के बाद सबसे कम है। उस समय इसपर 8.5 प्रतिशत ब्याज दिया गया था। ईपीएफओ ने अपने अंशधारकों को 2016-17 में 8.65 प्रतिशत, 2017-18 में 8.55 प्रतिशत का ब्याज दिया था। वित्त वर्ष 2015-16 में ब्याज दर 8.8 प्रतिशत थी। वित्त वर्ष 2013-14 और 2014-15 में ब्याज दर 8.75 प्रतिशत तथा 2012-13 में 8.5 प्रतिशत थी।

श्रम मंत्रालय को इस मामले में वित्त मंत्रालय से सहमति लेना जरूरी होता है। चूंकि ईपीएफओ रिटर्न मामले में भारत सरकार की गारंटी होती है, अत: वित्त मंत्रालय ब्याज दर की समीक्षा करता है ताकि ईपीएफओ की आय में किसी प्रकार की कमी से देनदारी नहीं बने।

वित्त मंत्रालय ईपीएफ ब्याज दर को लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) और डाकघर बचत जमा योजनाएं जैसी अन्य लघु बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज के अनुरूप करने के लिए श्रम मंत्रालय से कहता रहा है।

विलय के खिलाफ 27 मार्च को हड़ताल

टी ई नरसिम्हन
चेन्नई, 5 मार्च

ऑल इंडिया बैंक एम्पलोयीज एसोसिएशन (एआईबीईए) और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (एआईबीओए) ने 27 मार्च को हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। यह हड़ताल बैंकों के विलय के सरकार के फैसले का विरोध करने के लिए बुलाया जाएगा। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विलय को मंजूरी दी थी।

बैंक काफी संख्या में दबावग्रस्त ऋणों के बोझ का सामना कर रहे हैं। महासचिव सीएच वेंकटचलम ने कहा कि एक ओर जहां 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 1,50,000 करोड़ रुपये का कुल सकल लाभ हुआ था, दबावग्रस्त ऋणों के लिए 2,16,000 करोड़ रुपये के कुल प्रावधान आदि करने से अंत में उन्हें 66,000 करोड़ रुपये का शुद्ध नुकसान उठाना पड़ा था।

समाधान योजना से हल होंगे सभी कर विवाद

दिलाशा सेठ
नई दिल्ली, 5 मार्च

प्रत्यक्ष कर समाधान योजना में समूचे कर विवाद का समाधान किया जाएगा। इस योजना को अधिसूचित किया जाना अभी बाकी है। इसके प्रभावी होने के बाद एक आदेश में किसी मुद्दे को छांटने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यह स्पष्टीकरण केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से गुरुवार को जारी की गई 55 सहजता से पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) का हिस्सा है।

अपीलकर्ता को अनिवार्य तौर पर सभी मामलों के समाधान का विकल्प चुनना होगा और तब जाकर ही वह एफएक्यू पर स्पष्टीकरण दायर करने के योग्य बन पाएगा।

विवाद से विश्वास योजना के तहत करदाताओं को योजना के तहत भुगतान योग्य कर में अतिरिक्त चुकाई गई राशि वापस मिलेगी। यह नियम उस मामले में प्रभावी होगा जहां मुकदमेबाजी के दौरान करदाता ने पहले ही विवादित कर का भुगतान कर दिया है। इन्हीं स्पष्टीकरणों में से एक में कहा गया है, 'अपीलकर्ता अधिनियम की धारा 244ए के तहत बिना ब्याज के रिफंड पाने का हकदार होगा।'

लोकसभा में बुधवार को विधेयक को पारित कर दिया था। धन विधेयक होने के कारण इसके लिए राज्य सभा की मंजूरी जरूरी नहीं है। हालांकि, इसे उच्च सदन में भेजा जाएगा जो अधिनियम में बदलावों की सिफारिश कर सकता है लेकिन उन्हें मानना या नहीं मानना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करेगा। जिसके बाद इसे अधिसूचित करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। योजना से अधिकतम लाभ हासिल करने के लिए मूल्यांकनकर्ताओं के पास मुश्किल से पंद्रह दिनों का वक्त होगा। 31 मार्च तक भुगतान किए जाने की स्थिति में जहां पूरे ब्याज और जुर्माने की राशि को माफ कर दिया जाएगा वहीं उसके बाद 30 जून तक भुगतान करने पर विवादित राशि के अतिरिक्त 10 फीसदी का भुगतान करना होगा।

ऐसे करीब 4,00,000 से अधिक मामले लंबित हैं जिसमें से कम से कम 9.3 लाख करोड़ रुपये की कर राशि विवादों में फंसी है।

योजना अधिसूचित होना अभी बाकी

- यह स्पष्टीकरण केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से गुरुवार को जारी की गई 55 सहजता से पूछे जाने वाले प्रश्नों का हिस्सा
- करदाताओं को योजना के तहत भुगतान योग्य कर में अतिरिक्त राशि वापस मिलेगी

बहरहाल अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (एएआर) के पास लंबित मामलों को योजना के तहत कवर नहीं किया गया है लेकिन ऐसे मामलों में इसका फायदा मिलेगा जिनके खिलाफ अपील दायर की गई है और एएआर के आदेश में कर देयता निर्धारित की गई है।

बोर्ड ने एक उदाहरण देकर कहा, 'समझने के लिए, यदि एएआर ने एक आदेश दिया है कि भारत में स्थायी प्रतिष्ठान (पीई) है लेकिन ऐसे पीई के सिर पर पड़ने वाले रकम की जिम्मेदारी का एओ ने अब तक निर्धारण नहीं किया है, तो उन मामलों को कवर नहीं किया जाएगा क्योंकि अब तक कुल आय का निर्धारण नहीं हुआ है।'

योजना के तहत ब्याज, जुर्माना माफी और 31 जनवरी, 2020 तक आयकर अपीलीय अधिकरण (अपील) आयुक्त, उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय के पास लंबित इन विवादों के समाधान के लिए अभियोग चलाने की पेशकश की गई है। इसमें आयकर विभाग की ओर से दायर अपील में मुख्य कर राशि पर 50 फीसदी छूट देने की भी पेशकश की गई है।

सीबीडीटी ने स्पष्ट किया कि कीमत समायोजन स्थानांतरण करने के संबंध में विवाद के समाधान का असर द्वितीयक समायोजन पर नहीं पड़ेगा। द्वितीयक समायोजना से आशय उस अतिरिक्त रकम के प्रत्यावासन से है जो कर अधिकारियों द्वारा समायोजन किए जाने के बाद एमएनसी अपने पास रखती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सहायक इकाइयां अपने स्थानांतरण कीमत विवादों को योजना के तहत समाधान कर सकते हैं लेकिन उन्हें समूची विवादित राशि भारत वापस लाना होगा। अन्यथा, भारत में वापस नहीं लाए गए रकम को सहायक इकाइयों से मुख्यालय को ऋण लेने के तौर पर लिया जाएगा जिसपर ब्याज का भुगतान किया जाना है।

शार्दुल अमरचंद मंगलदास ऐंड कंपनी में पार्टनर अमित सिंघानिया ने कहा कि स्थानांतरण कीमत विवादों के मामले में द्वितीयक समायोजन को लागू करने का पहलू योजना से उम्मीद किए जा रहे लाभों को ढंक देता है।

पांच हजार कंपनियों से विभाग ने साधा संपर्क

श्रीमी चौधरी
नई दिल्ली, 5 मार्च

आयकर विभाग ने विवाद से विश्वास या प्रत्यक्ष कर विवाद निपटान योजना का लाभ उठाने के लिए अब तक 5,627 कंपनियों से संपर्क साधा है। इन कंपनियों में बड़े करदाता, मुख्य रूप से विदेशी बैंक शामिल हैं, जिनके अंतरराष्ट्रीय करों से संबंधित विवाद हैं।

विभाग द्वारा तैयार शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 1,730 करदाताओं ने योजना को अपनाने की सहमति जताई है। इन 1,730 मामलों में 1,578 करोड़ रुपये का कर फंसा हुआ है। इस रिपोर्ट पर 28 फरवरी को हुई बैठक में चर्चा की गई थी। यह बैठक ओवरसाइट कमेटी ने बुलाई थी, जो विवाद से विश्वास योजना की निगरानी के लिए बनाई गई आंतरिक समिति है। एक अधिकारी ने कहा कि समिति को विभिन्न रणनीतियों, विभिन्न न्यायिक मंचों में लंबित याचिकाओं की ताजा संख्या और योजना को सफल बनाने की आगामी कार्ययोजना के बारे में जानकारी दी गई।

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विभिन्न फोरम में प्रत्यक्ष कर के 80,332 मामले लंबित हैं, जिनमें 4.5 लाख करोड़ रुपये का कर फंसा हुआ है। इन फोरम में आयुक्त याचिकाएं, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और विवाद समाधान पैनल आदि शामिल हैं। पहले यह माना जा रहा था कि विभिन्न अदालती मंचों पर 4.8 लाख मामलों में 9 लाख करोड़ रुपये का कर फंसा हुआ है।

सूत्रों ने कहा कि सरकार इस योजना के तहत सभी मामलों का निपटारा करना चाहती है और वह इस महीने के अंत तक कम से कम दो लाख करोड़ रुपये प्राप्त होने की उम्मीद कर रही है। अधिकारी ने कहा कि हालांकि इसे लेकर स्थिति इस महीने के मध्य तक साफ होगी। उस समय तक योजना को लेकर करदाताओं की प्रतिक्रिया का पता चल जाएगा।

संक्षेप में

अमेरिका ने पांच में से एक वीजा आवेदन ठुकराया

अमेरिका ने वर्ष 2019 में एच1बी वीजा के लिए हर पांच नए आवेदनों में से एक आवेदन को ठुकराया। इसमें टीसीएस और इन्फोसिस जैसी भारतीय आईटी कंपनियों की ओर से किए जाने वाले आवेदनों को खारिज करने की दर अन्य अमेरिकी कंपनियों के मुकाबले अधिक है। यह गैर-आव्रजक वीजा है जो विदेशी कर्मचारियों को नौकरी पर रखने की सुविधा प्रदान करता है। *भाषा*

एचएसबीसी ने की अनुषंगी के परिसमापन की मांग

वैश्विक बैंकिंग कंपनी एचएसबीसी ने बकाया कर्ज नहीं चुका रही आईएलऐंडएफएस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की एक विदेशी अनुषंगी को बंद करने के लिए सिंगापुर की एक अदालत में याचिका दाखिल की है। *भाषा*

दुनिया भर में अति धनाड्य लोगों की संख्या 2019 में 6.4 प्रतिशत बढ़ी

पुनीत वाधवा
नई दिल्ली, 5 मार्च

विश्व में 2019 में अति धनाड्य (अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स या यूएचएनडब्ल्यूआई) लोगों की संख्या में 31,000 लोग और जुड़ गए हैं। नाइट फ्रैंक की 2020 की वेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक 3 करोड़ डॉलर या इससे ज्यादा संपत्ति वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 5,13,200 हो गई है। इस तरह से 2018 की तुलना में अति धनाड्यों की संख्या 2019 में 6.4 प्रतिशत बढ़ी है।

नाइट फ्रैंक के मुताबिक इस सूची में भारत 12वें स्थान पर है और 2019 में यहां इस श्रेणी में 5,986 लोग शामिल रहे हैं, जिनकी संख्या 2024 तक बढ़कर 10,354 हो सकती है। वहीं 2024 तक भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़कर 113 हो सकती है, जो 2019 में 104 है। संपत्ति की श्रेणी में भारत के अति धनाड्य लोग इक्विटी में निवेश को लेकर ज्यादा आक्रामक रहे और 72 प्रतिशत ने संपत्ति की इस श्रेणी में निवेश की इच्छा जताई। वहीं इक्विटी निवेश में वैश्विक रूप से औसतन 29 प्रतिशत लोगों ने दिलचस्पी ली।

इस सर्वे में अक्टूबर और नवंबर 2019 में 620 निजी बैंकरों व संपत्ति सलाहकारों की प्रतिक्रिया ली गई, जो 200 देशों व इलाकों के अति धनाड्य ग्राहकों की 3.3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा संपत्ति का प्रबंधन करते हैं।

भारत की स्थिति

नाइट फ्रैंक के मुताबिक उत्तरी अमेरिका का अति धनाड्यों की सूची में दबदबा है, जहां यूरोप की तुलना में ऐसे लोगों की संख्या दोगुनी है। वहीं दूसरी तरफ एशिया बहुत तेजी से यूरोप के करीब पहुंच रहा है और रियल्टी ब्रोकिंग व कंसल्टिंग फर्म का अनुमान है कि 2024 तक यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संपत्ति का केंद्र बन जाएगा, जहां 5 साल की वृद्धि 44 प्रतिशत होगी।

रिपोर्ट में कहा गया है, 'बहरहाल एशिया में अति धनाड्य लोगों की संख्या में बढ़ोतरी के बावजूद उत्तर अमेरिका की तुलना में आकार में इनकी संख्या आधी ही होगी, जहां इसी अवधि के दौरान 22 प्रतिशत बढ़ोतरी का अनुमान है।'

नाइट फ्रैंक को उम्मीद है कि अगले 5 साल में अति धनाड्य लोगों की संख्या 27 प्रतिशत बढ़कर 6,49,331 हो जाएगी। इस मामले में तेजी से बढ़ रहे देशों में 6 एशिया में हैं, जिसमें 73 प्रतिशत वृद्धि के साथ भारत पहले स्थान पर है। वहीं इस श्रेणी में यूरोप के 5 (47 प्रतिशत वृद्धि के साथ स्वीडन पहले स्थान पर) और अफ्रीका के 3 (66 प्रतिशत वृद्धि के साथ मिश्र पहले स्थान पर) देश शामिल हैं।

भारत में बढ़ रहे अमीर

- नाइट फ्रैंक के मुताबिक **5** साल में अति धनाड्य लोगों की संपत्ति **73** प्रतिशत बढ़ी
- सर्वे के मुताबिक भारत का अमीर तबका इक्विटी निवेश में ज्यादा आक्रामक
- विश्व में **3** करोड़ डॉलर या इससे ज्यादा संपत्ति वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर **5,13,200** हो गई
- भारत 12वें स्थान पर, **2019** में इस श्रेणी में **5,986** लोग शामिल हैं, जिनकी संख्या **2024** तक बढ़कर **10,354** हो सकती है

पोर्टफोलियो आवंटन

अति धनाड्य लोग कहां निवेश करते हैं? नाइट फ्रैंक के सर्वे के मुताबिक अति धनाड्य लोग अपने पोर्टफोलियो का 27 प्रतिशत निवेश रियल एस्टेट में, 23 प्रतिशत निवेश बॉन्ड मे और 17 प्रतिशत स्थाई संपत्तियों में करते हैं।

सर्वे में कहा गया है, 'हमारे दृष्टिकोण सर्वे के मुताबिक अति धनाड्यों में से 23 प्रतिशत पोर्टफोलियो इक्विटी में करते हैं, जिसका मतलब यह है कि उनकी संपत्ति बढ़ाने में इसकी भूमिका ज्यादा होती है। अति धनाड्यों की कुल संपत्ति का बड़ा हिस्सा आवासीय संपत्तियों में जाता है, जो करीब एक तिहाई है।'

शहरों में तीन प्रमुख मैट्रिक्स संपत्ति, निवेश और जीवन शैली के आधार पर सर्वे किया गया, जिसमें न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस 5 वैश्विक शहरों में शामिल हैं, जिनके बाद हॉन्गकॉन्ग और लॉस एंजेलिस आते हैं। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में कहा गया है, 'शीर्ष 20 शहरों में उत्तर अमेरिका के 8, एशिया और यूरोप के 5-5 शहर हैं। इसमें रूस के शहर मॉस्को की नई प्रविष्टि है। वहीं सिडनी ने ऑस्ट्रेलिया की मौजूदगी बनाए रखी है।'

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 13 अंक 17

अतार्किक प्रतिबंध

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को निर्णय दिया कि क्रिप्टोकरेंसी कारोबारियों के खातों और उनके लेनदेन से जुड़े बैंकों और एक्सचेंज पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा लगाया गया प्रतिबंध असंवैधानिक है। अप्रैल 2018 में लगे प्रतिबंध ने भारतीय क्रिप्टोकरेंसी बाजार की कमर तोड़ दी थी। इंटरनेट ऐंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमए) ने इसे चुनौती दी थी और तीन सदस्यीय पीठ ने प्रतिबंध हटा दिया। आईएएमए ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी कारोबार वैध कारोबारी गतिविधि है और यह आरबीआई के क्षेत्राधिकार से बाहर है क्योंकि इन परिसंपत्ति को मुद्रा के बजाय जिंस के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह निर्णय इस उद्योग के लिए राहत लेकर आया है लेकिन अभी अनिश्चितता है। कहा जा रहा है कि सरकार कानून लाकर क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन को आपराधिक बनाने जा रही है। जुलाई 2019 में एक पैनल ने इसकी अनुशंसा की थी।

बहरहाल सर्वोच्च अदालत के निर्णय का कई वजह से स्वागत किया जाना चाहिए। दलील है कि क्रिप्टोकरेंसी को एक वर्ग के रूप में प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक इस विषय पर बंटे हुए हैं। जापान, कोरिया और कई अन्य देश कुछ विशिष्ट क्रिप्टोकरेंसी को वैध मानते हैं और उन्होंने इनके लेनदेन को लेकर कड़े नियम बनाए हैं। उदाहरण के लिए क्रिप्टोकरेंसी से सीमापार लेनदेन आसान हो सकता है। ब्लॉकचेन तकनीक कई क्रिप्टोकरेंसी को एक साथ लाती है। वह काफी विविधतापूर्ण और नवाचारी है। ब्लॉकचेन तकनीक इलेक्ट्रॉनिक बही खाता तैयार करती है जहां हर लेनदेन रिकॉर्ड होता है और अनेक लोग गोपनीयता रखते हुए उसका प्रमाणन कर सकते हैं। यह फर्जी तथ्यों को तुरंत पकड़ लेता है और लेनदेन के दोहराव को नकार देता है। ब्लॉकचेन की अवधारणा बिटकॉइन में गोपनीय लेनदेन के प्रमाणन के लिए तैयार की गई थी। उसके बाद से इसे कई अन्य उद्देश्यों से काम में लाया जाने लगा। गोपनीय पक्षों के बीच कमजोर अनुबंध प्रवर्तन, नगर निकायों के काम के प्रमाणन और विलासितापूर्ण वस्तुओं मसलन कलाकृतियों, डिजाइनर कपड़ों और पुरानी शराब आदि के प्रमाणन में भी इसका इस्तेमाल होने लगा।

कई वित्तीय सेवा प्रदाताओं और निवेश बैंकों ने भी ब्लॉकचेन को अपनाया है। वे इसका इस्तेमाल आंतरिक अंकेक्षण में करते हैं क्योंकि इससे कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी बहुत मुश्किल हो जाती है। क्रिप्टोकरेंसी बंद करने से इस क्षेत्र में नवाचार भी ठप पड़ गया। कई क्रिप्टोकरेंसी मसलन बिटकॉइन, इथीरियम और रिपल आदि वैकल्पिक निवेश के रूप में भी मूल्य रखती हैं। इन मुद्राओं ने 2012-13 में कारोबारियों को वैश्विक अस्थिरता से बचाव मुहैया कराया और बीते छह महीनों में भी ऐसा ही हुआ। सन 2017-18 के आखिर में भारतीय एक्सचेंजों पर हर महीने 3 लाख नए कारोबारी जुड़ रहे थे और भारत भर में कारोबार का आकार बढ़ रहा था। उस प्रतिबंध ने भारतीयों को इन उपायों का लाभ लेने से वंचित कर दिया और भारतीय एक्सचेंज मजबूरी में बंद हो गए। इससे रोजगार और निवेश को नुकसान पहुंचा। निश्चित तौर पर क्रिप्टोकरेंसी में बहुत अस्थिरता है और समझ की कमी से कारोबारियों को भारी नुकसान हो सकता है। परंतु यह बात तो अधिकांश वित्तीय परिसंपत्तियों पर लागू होती है। कारोबारियों और निवेशकों को इन जोखिमों के साथ जीना सीखना होगा। प्रतिबंध थोपने के बजाय बेहतर यह होगा कि निवेशकों को जोखिमों के प्रति जागरूक किया जाए और धोखाधड़ी और घोटालों पर नजर रखी जाए। स्थानीय क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों से कहा जा सकता है कि वे शेयर बाजार की तरह केवाईसी (ग्राहक को जानें) मानकों का पालन करें। स्थानीय सर्वर पर भंडारित डेटा नियामकों के लिए भी आसानी से उपलब्ध होगा। ऐसे में कर वंचना और धनशोधन की आशंका नहीं होनी चाहिए। जीवंत क्रिप्टोकरेंसी देश के वित्तीय क्षेत्र की मददगार साबित हो सकती है।

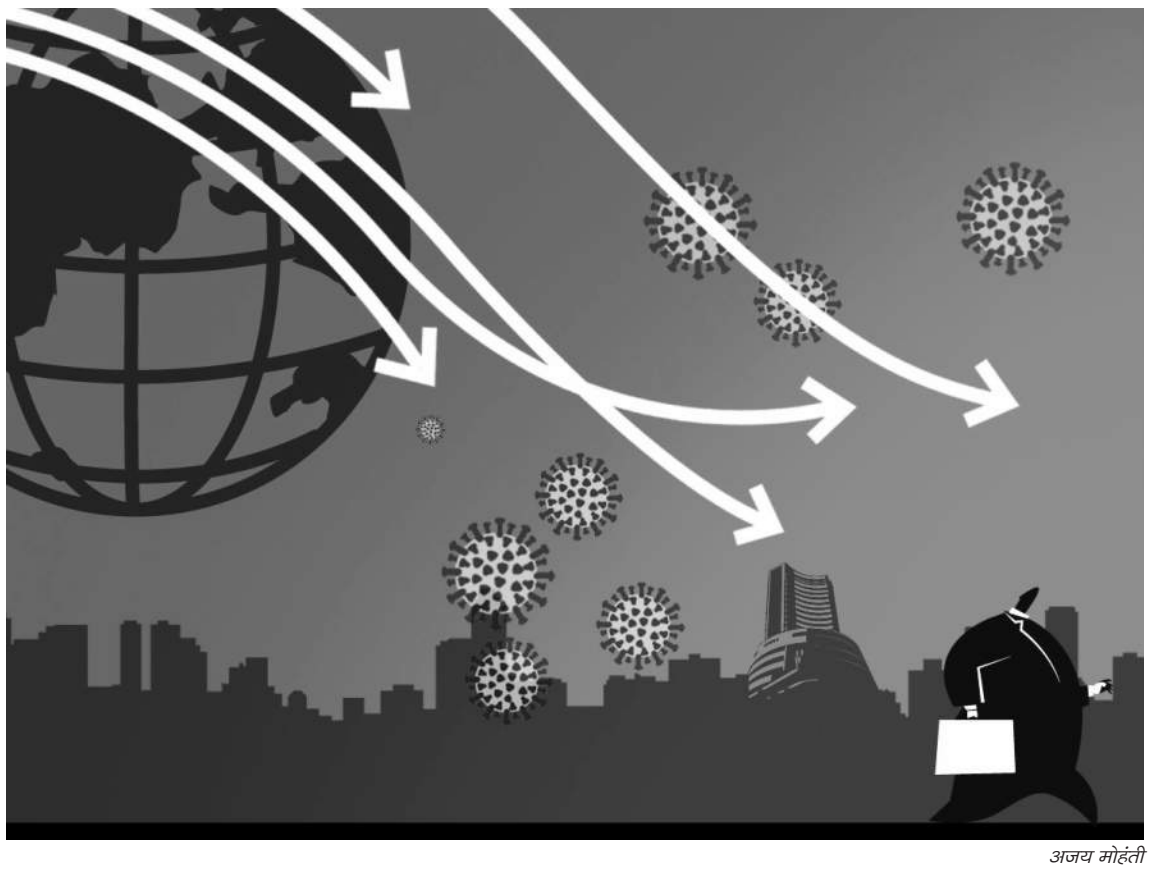

अजय मोहंती

कमजोर अर्थव्यवस्था पर कोरोना का जल्द असर

कोरोनावायरस के खतरे और वैश्विक बाजार में गिरावट के बीच ताजा आर्थिक आंकड़े परेशान करने वाली तस्वीर पेश करते हैं। विस्तार से बता रहे हैं **देवाशिष बसु**

जैसा कि समय-समय पर होता रहा है, शेयर बाजार में एक बार फिर गिरावट का दौर है। हर बार इसके पीछे अलग वजह होती है। इस बार तात्कालिक वजह है कोरोनावायरस। इस महामारी की शुरुआत दिसंबर में चीन से हुई लेकिन अब इसके चलते दुनिया भर में भय का माहौल बना हुआ है। चूंकि चीन में संकट सबसे अधिक गहरा है इसलिए वैश्विक मांग और आपूर्ति पर असर पड़ना स्वाभाविक है। चीन न केवल वैश्विक निर्यात में योगदान करता है बल्कि वह बड़ा आयातक भी है। वैश्वीकरण के 30 वर्षों के बाद तमाम अर्थव्यवस्थाओं के बीच विनिर्माण, व्यापार और पर्यटन के संबंध मजबूत हुए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि दुनिया के एक हिस्से में उपजा संकट आसानी से हजारों मील दूर फैल सकता है। इसलिए 19 दिसंबर के बाद से एसऐंडपी में 12.4 फीसदी, निक्केई में 9.65 फीसदी और निफ्टी में 7.5 फीसदी की गिरावट आई है।

असली चिंता बाजार के ध्वस्त होने की या भारत पर कोरोनावायरस के प्रभाव की नहीं है। बड़ी चिंता है हमारी अर्थव्यवस्था के आगे चलकर और कमजोर होने की। अब यह स्पष्ट होता जा रहा है। गत शुक्रवार को सरकार ने कहा कि तीसरी तिमाही में देश की जीडीपी वृद्धि दर गिरकर 27 तिमाहियों के निचले स्तर पर आ गई और यह 4.7 फीसदी रही। जबकि दूसरी तिमाही में इसका संशोधित अनुमान 5.1 फीसदी था।

पहला, निर्माण क्षेत्र पहले ही संकट में है और लगातार दो तिमाहियों में इसमें गिरावट आई है। दूसरा, आंकड़ों की नई शृंखला आने के बाद पहली बार उपयोगिता क्षेत्र में गिरावट दर्ज की गई है। तीसरा, विनिर्माण क्षेत्र में कोई वृद्धि देखने को नहीं मिली। चौथा, लगातार दूसरी तिमाही में निर्यात में गिरावट आई है। पांचवां, पूंजी निवेश में लगातार दूसरी तिमाही में गिरावट आई। यह तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर 5.2 फीसदी रही जो बेहद कम थी। यह बाजार कारोबारियों के लिए झटका होगा क्योंकि वे त्रासद बजट को परे कर चुके थे और बाजार सूचकांक लगभग उच्चतम स्तर पर थे।

पिछली तिमाही के संशोधित आंकड़े बताते हैं कि वृद्धि आगे और कमजोर होगी। वायरस के खतरे और वैश्विक बाजार में गिरावट के बीच ताजा आर्थिक आंकड़े डरावनी तस्वीर पेश करते हैं। खासतौर पर यह देखते हुए कि दिसंबर तिमाही किसी भी देश में सबसे मजबूत होती है।

कमजोर आर्थिक प्रतिरक्षा

स्पष्ट है कि भारतीय बाजार अपनी ऊर्जा गंवा चुके थे और कोरोनावायरस ने बाहरी झटकों के प्रति उसकी कमजोर प्रतिरक्षा को उजागर कर दिया है। इस कमजोर प्रतिरक्षा के लिए बीते छह वर्ष के दौरान उच्चतम स्तर पर कमजोर नीति निर्माण उत्तरदायी है। प्रधानमंत्री कार्यालय से नीचे, नेताओं और बाबुओं तक ने अतीत में तो गलतियां की ही हैं, उन्होंने हाल में भी कई बुरी गलतियां की हैं। वे न केवल पुराने ढह रहे ढांचे को सुधारने में नाकाम रहे बल्कि उसे और कमजोर किया। ऐसे में आज हम बीते छह साल की तुलना में अधिक संवेदनशील स्थिति में हैं। इन बातों ने अर्थव्यवस्था को कमजोर किया है।

मोदी सरकार व्यापक तौर पर अनुत्पादक सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कोई हल नहीं तलाश कर पाई है। न तो कोई सार्थक विनिवेश हुआ है और न ही कोई अहम सामरिक विनिवेश सामने आया। विनिवेश के नाम पर केवल एक सरकारी कंपनी के शेयर दूसरी कंपनी को बेचने जैसी घटनाएं घटी हैं। इस बीच लाभांश के रूप में सरकारी कंपनियों से अरबों रुपये निकाले गए। कई कंपनियों के पास तो अब वेतन देने तक के पैसे नहीं हैं। सरकारी बैंकों की हालत भी जस की तस है। बस कुछ बैंकों का आपस में विलय किया गया है। उनका स्वामित्व, भ्रष्टाचार और प्रबंधन की जवाबदेही की कमी जस की तस है। इन बैंकों को चालू रखने के लिए करदाताओं की अरबों रुपये की राशि इनमें निवेश की गई।

बजट में दिखाई जाने वाली उदारता थमने का नाम ही नहीं ले रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संप्रग की योजनाओं का नाम बदलकर उनका विस्तार कर दिया। उन्होंने विभिन्न वरीयता प्राप्त वर्गों को काफी कुछ दिया। पिछली कांग्रेस सरकार के तर्ज पर ही उनकी सरकार ने मुद्रा ऋण मेले की शुरुआत की। नतीजा यह कि राजकोषीय घाटे में इजाफे को अब आंकड़ों की बाजीगरी से छिपाया जा रहा है।

न केवल कर आतंक का सिलसिला जारी रहा बल्कि अब इसे कानून में स्थान दे दिया गया है। उच्च कर दर, समस्या ग्रस्त तंत्र और वस्तु एवं सेवा कर कानून के पुरातन प्रावधानों के चलते भी सरकार का राजस्व नहीं बढ़ा। बल्कि इनके चलते कारोबारियों की दिक्कतों में अवश्य इजाफा हुआ। रॉयटर्स की गत सप्ताह प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक राजस्व में गिरावट आ रही है और इस बीच कर अधिकारी तीन साल पुराने नोटबंदी के मामलों को उठा रहे हैं।

आभूषण विक्रेताओं को कर नोटिस मिले हैं और उनसे उस पैसे के बारे में पूछताछ की जा रही है जो उन्होंने नोटबंदी के समय सोना बेचकर कमाए। रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में करीब 15,000 आभूषण कारोबारियों को ऐसे नोटिस भेजे गए हैं। यहां पर इन्फोसिस के एक पूर्व निदेशक की बात याद करना उचित रहेगा। उन्होंने कहा था कि कर अधिकारी हर किसी को कर चोरी करने वाला समझते हैं और खुद को निगरानीकर्ता। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी ने 30 से अधिक देशों में रिटर्न फाइल किए हैं लेकिन कहीं भी करदाताओं से इतना बुरा व्यवहार नहीं होता जितना भारत में।

इसके अलावा केंद्र सरकार ने कई महंगी देशव्यापी योजनाओं की भी शुरुआत की है जिनके चलते परेशानी खड़ी हो रही है। आधार के लिए कहा जा रहा था कि इससे सब्सिडी की बरबादी रुकेगी लेकिन यह भी कारगर साबित नहीं हुई। यह गरीबों को ही नुकसान पहुंचा रही है जिनकी इसे मदद करनी थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (पी चिदंबरम के दिमाग की उपज) ने सामाजिक तनाव बढ़ाया है। इस बीच अफसरशाही और गड़बड़ी युक्त दिवालिया ढांचे ने अफरातफरी का माहौल बनाया है।

कुल मिलाकर देखें तो वादा न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन का था लेकिन हुआ इसका उलटा है। विकास और अच्छे दिन दूर रहे जबकि सरकार का हस्तक्षेप बढ़ा है। संस्थाओं का पराभव हुआ है और अर्थव्यवस्था की प्रतिरक्षा कमजोर पड़ी है। ऐसे में बाहरी झटकों से बचाव मुश्किल हुआ है। यदि कोरोनावायरस का हमला नहीं हुआ होता तो भी कमजोर अर्थव्यवस्था का खमियाजा तो भुगतना ही पड़ता।

जैक वेल्च की विरासत और उनके गुणों का अनुकरण

जिंदगीनामा

कनिका दत्ता

जैक वेल्च का गत 1 मार्च को निधन हो गया। भारत के पुरुष प्रधान और ज्यादातर पारिवारिक स्वामित्व वाले कारोबारी जगत में उनके ढेरों अनुयायी थे। इन्हें प्रबंधन को लेकर वेल्च का मर्दाना रवैया बहुत पसंद आता था जिसे उन्होंने बेहद सावधानीपूर्वक गढ़ा था। चाहे मालिक प्रबंधक हों या पेशेवर प्रबंधक, सभी यह इच्छा रखते कि काश वे 'न्यूट्रॉन' जैक की तरह सीधी बात करने वाले, लोगों को बिना हिचक काम पर रखने और निकालने वाले और अपनी मर्जी से कारोबार बंद करने वाले होते। लेकिन दुख की बात है कि इनमें से कम ही लोग अपने आदर्श के उन गुणों का अनुकरण करते हैं जिनके बारे में ज्यादा लोग जानते भी नहीं होंगे। वह गुण है ऐसे लोगों के साथ बेहतर ढंग से काम करना जिनसे उनकी नहीं पटती और अपने उत्तराधिकारी का सतर्कतापूर्वक चयन करना।

उनके नेतृत्व में जनरल इलेक्ट्रिक (जीई) ने जो अप्रत्याशित प्रदर्शन किया उसका श्रेय काफी हद तक जीई कैपिटल को भी जाता है। इसे कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। जीई की आय का 40 फीसदी हिस्सा वित्तीय सेवा क्षेत्र की इस बड़ी फर्म से आता है। फॉर्च्यून पत्रिका के एक आकलन के मुताबिक यदि कैपिटल नहीं होती तो सन 1991 से 1996 के बीच जीई का राजस्व बमुश्किल 4 फीसदी वार्षिक की दर से बढ़ता। जबकि इसकी बदौलत यह 9.1 फीसदी रहा। पत्रिका ने यह भी कहा कि तमाम शेयरों में मामूली वृद्धि के बाद भी यदि जीई के शेयर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसकी वजह कैपिटल में वॉल स्ट्रीट का भरोसा ही है। बीते दो वर्ष में इसके शेयर 123 फीसदी ऊपर गए हैं जबकि एसऐंडपी 500 के शेयर केवल 63 फीसदी उछले हैं।

उक्त आलेख इन अप्रत्याशित आंकड़ों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति गैरी वेंट के इस्तीफा देने के एक वर्ष पहले छपा था। हालांकि उनके पद छोड़ने का प्रदर्शन से कोई लेनादेना नहीं था। कई लोग उन्हें बहुत मुंहफट, अपेक्षाएं रखने वाला और विस्तृत ब्योरों की चाह रखने वाला मानते हैं लेकिन उन्होंने ऐसे कारोबारी व्यवहार और प्रबंधन शैलियां स्थापित कीं जिन्होंने जीई को गति दी। उनके बॉस वेल्च ने उन्हें एक शानदार उद्यमी बताया।

वेल्च ने भले ही उनकी तारीफ की थी लेकिन सभी जानते थे कि दोनों की आपस में बनती नहीं थी। कई लोग यह जानकर चकित होंगे कि वेंट भी वेल्च के संभावित उत्तराधिकारियों की सूची में शामिल थे। वह इसलिए नाकाम रहे क्योंकि उन्हें तलाक के एक मामले में सार्वजनिक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। इसके बाद वेल्च ने उनसे इस्तीफा देने की मांग की और उन्होंने सन 1998 में इस्तीफा दे दिया। विडंबना यह है कि बाद में वेल्च खुद तलाक के ऐसे ही एक मामले में उलझ गए। उन्हें तो सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ के लिए फेडरल जांच का भी सामना करना पड़ा।

जी हजूरी की कॉर्पोरेट संस्कृति में यह सोचना भी मुश्किल है कि कोई भारतीय कंपनी, खासकर परिवार द्वारा प्रबंधित कोई कंपनी असहमत वरिष्ठ अधिकारी को बरदाश्त भी करेगा, उसे सितारा बनने देने या उत्तराधिकारी के रूप में चुनना तो दूर की कौड़ी है। भारत के बड़े कारोबारी संस्थानों में उत्तराधिकार के रुख पर विचार कीजिए: यदि उत्तराधिकारी परिवार से नहीं है या संस्थापक सदस्य नहीं है तो फिर आमतौर पर वह कोई टेक्नोक्रेट होता है जिस पर प्रवर्तक भरोसा कर सके।

प्रतिद्वंद्वी को बरदाश्त करना और बढ़ावा देना वेल्च की इकलौती विशेषता नहीं थी। उनकी उत्तराधिकार योजना भी विशिष्ट थी। वह 2001 में सेवानिवृत्त हुए लेकिन उन्होंने उत्तराधिकारी की तलाश सन 1994 में ही शुरू कर दी थी। इस कवायद को वरिष्ठ कार्याधिकारियों के आकलन की वार्षिक नियमित कवायद में मिला दिया गया था लेकिन उनके प्रदर्शन का लगातार आकलन किया गया।

यह एक अत्यंत विस्तृत प्रक्रिया थी जिसका वेल्च ने सूक्ष्म प्रबंधन किया, संभवत: उन्होंने बोर्ड को भयभीत करके अपने चुने हुए अंतिम तीन नामों को स्वीकार करने पर मजबूर किया। ये थे जेम्स मिकनर्नी जो एयरक्राफ्ट इंजन के कारोबार में थे, रॉबर्ट नार्डेली जो जीई बिजनेस के प्रमुख थे जो इलेक्ट्रिक उपकरणों के लिए टर्बाइन और जनरेटर बनाते थे और जेफ्री आर इमेल्ट, जो चिकित्सा उपकरण कारोबार में थे। इमेल्ट को सफलता भी मिली, शायद इसलिए क्योंकि उनकी उम्र तीनों में सबसे कम थी।

यह सही है कि चुने गए तीनों लोगों का करियर कोई चमकदार नहीं रहा। इमेल्ट जीई के लिए साधारण चयन साबित हुए। मिकनर्नी जो आगे चलकर बोइंग के सीईओ बने, उन्होंने नया मॉडल लॉन्च करने के बजाय 737 सीरीज को 737 मैक्स में उन्नत करने का निर्णय लिया। उन्होंने 2015 में इस्तीफा दे दिया और मैक्स के खराब प्रदर्शन के लिए आलोचना झेलने से बच गए। नार्डेली सन 2000 में होम डिपो के सीईओ बने और उन्होंने राजस्व को दोगुना कर दिया। हालांकि सात वर्ष बाद बोर्ड ने उन्हें इस्तीफा देने को कह दिया। वेल्च के विशाल कार्यकाल के दौरान उत्तराधिकार का मामला सहजतापूर्वक निपट गया। इसका अर्थ यह हुआ कि यह बड़ी वैश्विक कंपनी सहज तरीके से चल रही थी।

जब एक खोज समिति के युवा सदस्य और समूह के आंशिक हिस्सेदार को अचानक उत्तराधिकारी बनाया गया तो अचानक समस्याएं हल होने जैसी कोई बात नजर नहीं आई। हालांकि चार साल बाद उन्हें हटा दिया गया। वेल्च ने ऐसा कुछ नहीं किया किया किसी प्रबंध निदेशक को दोबार सेवा विस्तार दिया जाए जो बाद में चेयरमैन बने और ऐसे प्रबंध निदेशक को उत्तराधिकारी चुने जो उससे पहले सेवानिवृत्त हो जाए। ऐसा कोई प्रवर्तक नहीं जो चेयरमैन के रूप में पद छोड़े और उसके बाद बाजार नियामक द्वारा नियुक्ति नियम शिथिल करने पर दोबारा पद पर लौट जाए। वेल्च ने ऐसा कुछ नहीं किया लेकिन दुख की बात है कि उनको उनकी अनाकर्षक प्रबंधन शैली के लिए ज्यादा याद किया जाएगा।

कानाफूसी

मित्रता के बावजूद?

विपक्षी दल यह मुद्दा उठाने की योजना बना रहे हैं कि कैसे वीजा नियमों में हुए बदलाव पड़ोसी मुल्कों के साथ हमारे कूटनयिक रिश्तों को प्रभावित कर रहे हैं। खासतौर पर बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्तों को। एक साल से भी अधिक वक्त पहले भारत ने ऐसी वीजा व्यवस्था पेश की थी जिसमें भारत में तयशुदा से ज्यादा लंबे समय तक रुकने पर बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान के बहुसंख्यक वर्ग के लोगों यानी मुस्लिमों पर अधिक जुर्माना लगाने की बात शामिल थी। सूत्रों का कहना है कि बांग्लादेश इस बात से नाराज है कि नवंबर 2019 में भारत और बांग्लादेश के बीच गुलाबी गेंद से हुए टेस्ट मैच के बाद उसके खिलाड़ियों लिटन दास और सैफ हसन के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया। क्षेत्रीय विदेशी पंजीयन कार्यालय के अनुसार यदि पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान का कोई अल्पसंख्यक व्यक्ति दो वर्ष से ज्यादा की अतिरिक्त अवधि तक रुकता है तो 500 रुपये का जुर्माना, 91 दिन से दो वर्ष तक 200 रुपये जुर्माना और 90 दिन तक रुकने के लिए 100 रुपये जुर्माना उसे देना होगा। वहीं यदि वह व्यक्ति बहुसंख्यक वर्ग का है तो यह जुर्माना क्रमश: 35,000 रुपये, 28,000 रुपये और 21,000 रुपये है। विपक्षी दलों का कहना है कि बांग्लादेश मित्र राष्ट्र है और उसे पाकिस्तान के समकक्ष रखना सही नहीं।

आपका पक्ष

आतंरिक मामले में बाहरी हस्तक्षेप न हो

देशभर में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इस नए कानून को उच्चतम न्यायालय में भी चुनौती दी गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने भी अदालत में एक याचिका दायर की है। परिषद ने याचिका में कहा है कि नागरिकता संशोधन मामले की जब भी सुनवाई हो तो उसे भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए। विदेश मंत्रालय ने मानवाधिकार परिषद की याचिका का विरोध किया है। मंत्रालय का यह विरोध सही भी है, क्योंकि नागरिकता संबंधित मामले भारत के आंतरिक मामले हैं। मानवाधिकार परिषद का यह दखल भारत की सार्वभौमिकता पर भी सवाल खड़ा करता है। साथ ही यह भी दिखाता है कि भारत अपने देश में नागरिकता को परिभाषित करने में अक्षम है। मानवाधिकार परिषद का यह कदम देश में विरोध प्रदर्शन की फैली आग को और हवा देने का काम कर रहा है। ऐसी स्थिति में जब देश की संसद और लोकतंत्र व्यवस्था पर विदेश में सवाल उठ रहे हैं तो सभी विपक्षी दलों को इस हस्तक्षेप का भारी विरोध करना चाहिए। विपक्ष को वह समय याद करने की जरूरत है जब इसी मानवाधिकार परिषद ने कश्मीर का मुद्दा उठाया था तब उसे जवाब देने के लिए उस समय के विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा गया था। देश के मौजूदा हालात को देखते हुए फिर से वैसी ही एकता दिखाने की जरूरत आ पड़ी है।

प्रतीक बाजपेई, लखनऊ

कोलकाता में नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी *-पीटीआई*

अमेरिका और भारत के संबंध प्रगाढ़ हुए

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप हाल में भारत यात्रा पर आए थे और भारत के साथ कई करार किए। इससे दोनों देशों के सामरिक तथा व्यापारिक संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। दोनों देशों के बीच तीन अरब डॉलर का रक्षा क्षेत्र से संबंधित सौदा भी हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की औपचारिक वार्ता के बाद संयुक्त बयान जारी किया गया जिसमें आपसी रिश्ते को समग्र वैश्विक सामरिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने की घोषणा की गई। इस दौरे में अमेरिका के साथ हिंद-प्रशांत संकल्पना का प्रमुखता से जिक्र हुआ है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग के लिए चौपक्षीय शब्दावली का पहली बार औपचारिक रूप से इस्तेमाल हुआ है। चीन भारत के लिए चिंता का सबब रहा है लेकिन महत्त्वपूर्ण यह है कि भारत अब चीन और रूस की उतनी चिंता नहीं करता है।

कार्तिक त्यागी, ई-मेल से

अमेरिका के साथ से बढ़ेगी सुरक्षा

राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की यात्रा ऐसे समय में हुई जब अमेरिका में चुनाव होने हैं। अमेरिका में भारतीय समुदाय को न केवल सबसे मेहनती और अमीर समुदायों में माना जाता है बल्कि वहां बसे लगभग चौबीस लाख भारतीय अमेरिकी चुनाव में भी भूमिका निभाते हैं, जो एक बड़ी बात है। अमेरिका में भारतीयों का श्रम सिर्फ उन्हें ही लाभान्वित नहीं करता, इससे अमेरिका को भी फायदा होता है। अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने में भारत की सहायता तथा रक्षा क्षेत्र के सौदे दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। दोनों देशों के एक साथ शामिल होने से एशिया प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।

दुर्गेश शर्मा, गोरखपुर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

कोरोनावायरस से इस्पात क्षेत्र पर दबाव बढ़ने की आशंका

अदिति दिवेकर
मुंबई, 5 मार्च

कोरोनावायरस के प्रकोप से निकट भविष्य में इस्पात क्षेत्र में नरमी बढ़ने की आशंका है क्योंकि घरेलू इस्पात के दामों में पहले से ही चल रही नरमी से परिचालन मार्जिन को नुकसान पहुंच रहा है। इंडिया रेटिंग्स ऐंड रिसर्च ने यह संभावना जताई है। हालांकि एजेंसी का कहना है कि इसके प्रभाव की जटिलता चीन में बढ़ती वायरस की उग्रता और अवधि के साथ-साथ दुनिया के अन्य हिस्सों में इसके प्रसार पर निर्भर करेगी। वैश्विक आपूर्ति का यह बड़ा असंतुलन निश्चित रूप से व्यापक हो सकता है क्योंकि दुनिया का आधे से अधिक इस्पात उत्पादन और उपभोग अकेले चीन ही करता है।

उत्पादन में कमी करने के मौजूदा प्रयास के बावजूद चीन का इस्पात उत्पादन घटती उपभोक्ता मांग से आगे निकल सकता है जिसके परिणामस्वरूप स्टॉक का जमावड़ा होगा और दामों पर दबाव बनेगा। चीन के इस्पात उत्पादन में हेबी, लिओनिंग और शैंडोंग जैसे उत्तर-पूर्वी इस्पात विनिर्माण केंद्र वाले प्रांतों में ज्यादा कटौती नहीं देखी गई है। वहां हरेक प्रांत की क्षमता लगभग 10 करोड़ टन है। इसके अलावा चीन की कुल इस्पात क्षमता में 90 प्रतिशत का योगदान करने वाली ब्लास्ट फर्नेस को निष्क्रिय करना भी संभव नहीं है। हालांकि कमजोर विनिर्माण गतिविधियों और कुल खपत में मंदी के कारण चीन में इस्पात की मांग पर गंभीर प्रभाव नजर आया है।

अगर जापान, दक्षिण कोरिया, भारत और अमेरिका जैसे अन्य बड़े इस्पात उत्पादक राष्ट्रों में वायरस का प्रकोप बढ़ता है, तो मांग-आपूर्ति में असंतुलन भी बढ़ सकता है। फिलहाल भारतीय उत्पादकों की संयंत्र क्षमता उपयोग पर सीधे असर नहीं पड़ा है क्योंकि न तो चीन को इसका निर्यात किया जाता है और न ही वहां से कच्चे माल का प्रत्यक्ष रूप से कोई आयात होता है।

भारतीय इस्पात विनिर्माता अपने कुल उत्पादन का मात्र आठ प्रतिशत के आस-पास ही निर्यात करते हैं। इस कारण दुनिया में (चीन के अलावा) कोरोनावायरस के व्यापक प्रसार से इतना ही असर पड़ सकता है। वित्त वर्ष 20 के नौ महीने में वियतनाम (15 प्रतिशत), संयुक्त राष्ट्र अमीरात (आठ प्रतिशत), इटली (सात प्रतिशत), बेल्जियम (छह प्रतिशत) और नेपाल (छह प्रतिशत) भारत के शीर्ष पांच निर्यात गंतव्य रहे हैं तथा 415 अरब रुपये के कुल निर्यात में इनका हिस्सा 45 प्रतिशत रहा है।

कपास-धागे की कीमतों में कमी

कोरोनावायरस के कारण चीन को निर्यात रुकने का असर

दिलीप कुमार झा और
टी ई नरसिम्हन
मुंबई/चेन्नई, 5 मार्च

घरेलू बाजार में मांग से अधिक आपूर्ति की स्थिति पैदा होने के कारण पिछले एक महीने के दौरान कपास और धागे की कीमतों में 10 फीसदी तक की गिरावट आई है। घरेलू बाजार में अति आपूर्ति की स्थिति इसलिए पैदा हुई है क्योंकि चीन को निर्यात थम गया है। चीन में कोरोनावायरस फैलने के बाद दुकानें और फैक्टरियां बंद हैं।

कच्चे कपास के दाम गुजरात की गोंडल मंडी में घटकर 4,280 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गए हैं, जो करीब एक महीने पहले 4,755 रुपये प्रति क्विंटल थे। सूती धागे की कीमतें भी पिछले एक महीने में दो से तीन फीसदी टूटी हैं। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद सिंथेटिक धागे की कीमतों में भी 4-5 फीसदी गिरावट आई है।

कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष गणत्रा ने कहा कि वैश्विक स्तर पर आईसीई में कीमतें घटकर 60.50 सेंट पर आ गई हैं, जो 28 फरवरी को 71.5 सेंट थीं। इससे भी निर्यात मार्जिन पर असर पड़ा है। चीन में कोरोनावायरस फैलने की वजह से दुकानें और फैक्टरियां बंद हैं, जिससे भारत का कपास और धागा निर्यात बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

मुंबई के एक कपास निर्यातक अरुण सकसेरिया ने कहा, 'भारत से चीन को कपास और धागे का निर्यात थम गया है क्योंकि वहां से ऑर्डर ही नहीं आ रहे हैं। भारतीय निर्यातक भी निर्यात ऑर्डरों में कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। अगर माल भेजने के बाद गुणवत्ता या मात्रा से संबंधित कोई अड़चन पैदा होती है तो माल को बेचने के लिए चीन जाना मुश्किल होगा।'

चीन में कोरोनावायरस फैलने और इस बार कपास की गुणवत्ता अच्छी नहीं होने के कारण बाजार में रुझान कमजोर है, जिससे कपास और धागे की कीमतों में नरमी आ रही है।

कपास की कीमतों में गिरावट को मद्देनजर रखते हुए सरकार के स्वाामित्व वाला भारतीय कपास निगम (सीसीआई) थोक खरीदारों को पुराने स्टॉक पर 3,200 से 3,500 रुपये प्रति कैंडी (356 किलोग्राम) की छूट दे रहा है। कच्चे माल की कीमतों में गिरावट से कपड़ा मिलों को फायदा मिलने की संभावना है। उनका लाभ मार्जिन अगली कुछ तिमाहियों में बढ़ेगा।

फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मधु सुदन भागेरिया ने कहा, 'कोरोनावायरस फैलने से चीन में मांग और उत्पादन पर असर पड़ा है, जिससे कच्चे माल की कीमतों में नरमी आने लगी है। चीन में आपूर्ति श्रृंखला या पॉलिएस्टर धागे के उत्पादन में अवरोध से बाद में भारतीय पॉलिएस्टर विनिर्माताओं को निर्यात के ज्यादा मौके मिलेंगे।' पिछले महीने बजट में सरकार ने सिंथेटिक धागे के एक कच्चे माल प्यूरीफाइड टेरेफथालिक एसिड (पीटीए) पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया था।

पीटीए पर डंपिंग रोधी शुल्क खत्म होने से सिंथेटिक कपड़ा विनिर्माताओं के लिए परिदृश्य बदल गया है। चीन में मंदी के बावजूद भारतीय कपड़ा उद्योग में स्थिरता है। इक्रा के मुताबिक कोरोनावायरस फैलने से धागे के कम दाम मिल रहे हैं, जो फरवरी शुरू होने के बाद करीब 2-3 टूटे हैं। इससे पहले जनवरी में भारत के धागा निर्यात में कुछ समय सुधार आया था। उस समय निर्यात 10 करोड़ किलोग्राम पर पहुंच गया था। यह भारत के औसत मासिक निर्यात के समान था। जनवरी से पहले के 9 महीनों में धागे का निर्यात कमजोर रहा।

घरेलू कपास कताई उद्योग निर्यात विशेष रूप से चीन पर अत्यधिक निर्भर है। देश में उत्पादित कुल सूती धागे में से करीब 30 फीसदी का निर्यात होता है। हाल के वर्षों में एक-तिहाई निर्यात चीन को हुआ है।

इक्रा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और समूह प्रमुख (कॉरपोरेट सेक्टर रेटिंग) जयंत राय ने कहा, 'घरेलू रुई के दाम अंतरराष्ट्रीय कीमतों की तुलना में प्रतिस्पर्धी बने हुए हैं। इस समय घरेलू और वैश्विक कीमतों में अंतर चार फीसदी है, जो फरवरी में नौ फीसदी था। वैश्विक स्तर पर कपास की कीमतों में और गिरावट से घरेलू स्पिनर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धी नहीं रह जाएंगे। यह स्थिति वित्त वर्ष 2020 की पहली छमाही के समान है।'

- पिछले एक महीने के दौरान कपास और धागे की कीमतों में 10 फीसदी तक की गिरावट आई
- कच्चे कपास के दाम गुजरात की गोंडल मंडी में घटकर 4,280 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गए
- करीब एक महीने पहले 4,755 रुपये प्रति क्विंटल थे
- कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद सिंथेटिक धागे की कीमतों में भी 4-5 फीसदी गिरावट आई

गुजरात में दाम

दिन	रुपये/क्विं
12 फरवरी	4,755
13 फरवरी	4,755
14 फरवरी	4,755
15 फरवरी	4,755
17 फरवरी	4,605
18 फरवरी	4,730
19 फरवरी	4,705
25 फरवरी	4,480
26 फरवरी	4,280
27 फरवरी	4,255
28 फरवरी	4,250
2 मार्च	4,500
3 मार्च	4,255
4 मार्च	4,280

स्रोत- एगमार्कनेट डॉट जीओवी डॉट इन
संकलन- बीएस रिसर्च

मौसम के तेवर ने बढ़ाई किसानों की चिंता

संजीव मुखर्जी
नई दिल्ली, 5 मार्च

यह साल का वह वक्त है, जब उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत के लाखों किसान मौसम के उस प्रतिकूल बदलाव को देखने के लिए उत्सुकता से आसमान की ओर निहारते हैं जो अगले कुछ सप्ताह में काटी जाने वाली उनकी सर्दी की मूल्यवान फसल को नुकसान पहुंचा सकता है।

हालांकि फरवरी और मार्च में बेमौसमी बारिश तथा ओलावृष्टि कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन इस साल जोखिम कुछ ज्यादा है क्योंकि शायद कई सत्रों के बाद बहुत-सी फसलों का बाजार मूल्य पिछले सालों की तुलना में बेहतर है जिससे इस बात की कुछ उम्मीद जगी है कि वर्ष 2020 में कम से कम कुछेक फसलों की आमदनी पिछले कुछ सालों की तुलना में बेहतर रह सकती है।

कृषि में सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) और संबद्ध गतिविधियों के आंकड़े भी बेहतर तस्वीर की ओर इशारा कर रहे हैं। वर्ष 2019-20 में कृषि और संबद्ध गतिविधियों के जीवीए में मौजूदा कीमतों पर 11.3 प्रतिशत और स्थिर मूल्य पर 3.7 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है।

भारतीय मौसम विभाग के नवीनतम पूर्वानुमान से पता चलता है कि 5 और 6 मार्च के बीच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर तूफान और ओलावृष्टि के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है। आने वाले हफ्तों में बारिश के दायरे, प्रसार और आवृत्ति से यह निर्धारित होगा कि खड़ी फसलों को कितना नुकसान हुआ है।

मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में अब तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में ही बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि हुई है। केंद्र सरकार के कृषि आयुक्त डॉ. एसके मल्होत्रा ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, 'अगर फसल विकास अवस्था में है, तो कुछ हिस्सों में यह बेमौसमी बारिश वास्तव में कुछ फसलों के लिए फायदेमंद हो सकती है। अब तक हमें बड़े स्तर पर नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। इसके अलावा अब तक इतनी गंभीर ओलावृष्टि नहीं हुई है कि बेवजह डरा जाए।'

मध्य प्रदेश स्थित किसान समूह - राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के प्रवक्ता और संस्थापक सदस्य भगवान मीणा ने कहा कि हमारे पास मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के लगभग 60 और सिवनी में 40 गांवों के साथ-साथ दमोह, रीवा और शहडोल के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि के असर की सूचना है। अब तक सिंगरौली के अलावा गेहूं, चने और सरसों की खड़ी फसल के किसी भी बड़े नुकसान की खबर नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि अगर मध्य प्रदेश में अगले 15 दिनों तक मौसम अनुकूल बना रहता है, तो किसान बच जाएंगे क्योंकि राज्य में अधिकांश स्थानों पर गेहूं, सरसों और चने की कटाई शुरू हो चुकी है।

मौसम विभाग की चेतावनी

- पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर तूफान और ओलावृष्टि के साथ भारी वर्षा होने की संभावना
- आने वाले हफ्तों में बारिश के दायरे, प्रसार और आवृत्ति से यह निर्धारित होगा कि खड़ी फसलों को कितना नुकसान हुआ

कोरोना: दक्षिण एशिया में बढ़ी चिंता

विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत में संक्रमित लोगों की तादाद बढ़ने से दक्षिण एशिया क्षेत्र में बढ़ेंगी मुश्किलें

रॉयटर्स

देश में कोरोनावायरस संक्रमण की पुष्टि होने के साथ ही अब पूरा जोर पर्यटकों की जांच पर है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर सघन आबादी वाले दक्षिण एशिया में वायरस का प्रकोप बढ़ता है तो उस पर नियंत्रण करना काफी मुश्किल होगा क्योंकि यहां स्वास्थ्य सुविधाएं काफी कम है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में करीब 1.7 अरब लोग रहते हैं जो दुनिया की आबादी के 20 फीसदी से अधिक है। लेकिन इन देशों में कोरोनावायरस के मरीजों के लिए जरूरी गहन चिकित्सा वाली स्वास्थ्य सेवाएं मौजूद नहीं हैं।

वायरस से संक्रमित व्यक्ति को पहले से ही स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें मसलन डायबिटीज है तो इससे मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। नई दिल्ली में जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक हेल्थ के कार्यकारी निदेशक विवेकानंद झा कहते हैं, 'भारतीय समाज की संरचना के हिसाब से भी देखा जाए तो चीन और जापान जैसे देशों ने जिस तरह संक्रमित क्षेत्रों को बंद किया था वैसा यहां अच्छी परिस्थितियों में भी मुमकिन नहीं है।' देश में बुधवार को कोरोनावायरस के कुल 29 मामले की पुष्टि की गई थी।

वैश्विक स्तर पर कोरोनावायरस से 95,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और 3,200 से अधिक लोगों की मौत हो गई है जिनमें से ज्यादातर मौत चीन में हुई है। कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञों को इस बात का डर है कि हाल में संक्रमण के मामले बढ़ने के बावजूद देश के संक्रमण के वास्तविक आंकड़े में ज्यादा तेजी देखी जा सकती है।

मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरॉलॉजी के निदेशक अरुण कुमार ने बताया, 'ऐसी पूरी संभावना है कि देश में संक्रमण के पुष्ट मामलों के मुकाबले संक्रमितों की तादाद ज्यादा हो।' देश में डर का माहौल इस हफ्ते तब बढ़ गया जब देश के स्वास्थ्य मंत्री ने खुलासा किया कि 16 विदेशी पर्यटक जो देश में मध्य फरवरी से ही यात्रा कर रहे थे उनमें कोरोनावायरस संक्रमण जांच पॉजिटिव रहा है। पिछले हफ्ते अमेरिका के खुफिया सूत्रों ने भी बताया कि भारत की घनी आबादी में वायरस प्रसार की आशंका है।

देश की सरकार का कहना है कि यहां 10 लाख से ज्यादा यात्रियों की जांच की जा चुकी है और इससे जांच क्षमता में तेजी आई है और देश के सभी बड़े शहरों और अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर अलग वॉर्ड बनाया गया है। भारत के 1.3 अरब लोगों में से अनुमानत: 45 करोड़ लोग रोजाना सड़क और रेल व्यवस्था का इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वायरस का प्रसार एक बड़ी चुनौती हो सकती है।

भारत में मधुमेह के मरीजों की तादाद 7.7 करोड़ है और किडनी की बीमारी जैसी समस्या से मृत्यु दर ज्यादा हो सकती है। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सामुदायिक स्वास्थ्य के प्रोफेसर डॉ राजीव दासगुप्ता कहते हैं, 'भारत में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यह संक्रमण अगर किसी दीर्घकालिक बीमारी के साथ होता है तब इसका जोखिम ज्यादा होगा।' सरकार का कहना है कि देश में वायरस संक्रमण को रोकने की पर्याप्त क्षमता है।

पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी कोरोनावायरस के पांच मामले पाए गए हैं। एक शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य तैयारियों से निराश हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के महासचिव शाहिद मलिक कहते हैं, 'हमारे पास मानव संसाधन नहीं है और न ही एहतियात के लिए जरूरी सामान है। मौजूदा संसाधनों के साथ बड़ी आपात स्थिति से निपटने की हमारी क्षमता नहीं है।' बांग्लादेश ने अब तक संक्रमण की पुष्टि नहीं की है लेकिन सिंगापुर में पांच बांग्लादेशी कामगारों की संक्रमण जांच पॉजिटिव रही है। यहां के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि हवाईअड्डे और सीमाओं पर तीन लाख से अधिक लोगों की जांच की गई है। एक यात्री ने बताया कि जांच व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। सिंगापुर में काम करने वाले बांग्लादेशी फरीद यामिन ने कहा, 'हममें से ज्यादातर जांच व्यवस्था से बच सकते हैं। कल्पना करें, अगर कोई वायरस से संक्रमित व्यक्ति यहां आता है तब क्या होगा?'

- दक्षिण एशिया क्षेत्र में वायरस पर नियंत्रण करना मुश्किल, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं कम
- भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रहती है दुनिया की करीब 20 फीसदी आबादी
- पुरानी बीमारियों के साथ कोरोनावायरस का संक्रमण हो सकता है ज्यादा घातक

आगरा में गुरुवार को एक विदेशी पर्यटक की जांच करता एक स्वास्थ्यकर्मी

अमेरिका, ब्रिटेन का विमान किराया 20-30 फीसदी घटा

अनीश फडणीस

कोरोनावायरस का संक्रमण दुनिया भर में फैलने से कंपनियों के काम के सिलसिले से होनी वाली यात्रा में कटौती और घूमने के मकसद से की जाने यात्रा की योजनाएं टलने से यूरोप और अमेरिका के विमान यात्रा किराये में करीब 20-30 फीसदी तक की कटौती हुई है। हालांकि कुछ ही देशों में यात्रा प्रतिबंध लगा है जिनमें पूर्वी एशिया, सऊदी अरब और इटली जैसे देश शामिल हैं लेकिन कई संगठन और निजी स्तर पर भी लोग ब्रिटेन, अमेरिका और अन्य देशों की यात्राओं की बुकिंग टाल रहे हैं ताकि बीमारी से बचा जा सके।

एफसीएम ट्रैवल सॉल्यूशंस के प्रबंध निदेशक रक्षित देसाई कहते हैं, 'मई महीने के लिए इकॉनमी श्रेणी में मुंबई-न्यूयॉर्क से वापसी का टिकट अब 65,000 रुपये तक है। आमतौर पर यह किराया 80,000 रुपये तक होता है। इसी तरह इसी समान अवधि के दौरान बिना किसी ठहराव के लंदन से वापसी का टिकट 50,000 रुपये का है जो आम दिनों के मुकाबले 17 फीसदी सस्ता है।' इन दिनों फ्लाइट की बुकिंग पर असर पड़ा है और विमानन कंपनियों को आखिरी वक्त पर टिकट रद्द कराने जैसे रुझान दिख रहे हैं। इसके अलावा ग्राहक भी गर्मी के दिनों की यात्रा के लिए इंतजार करने की रणनीति अपना रहे हैं। एक यूरोपीय विमानन कंपनी के अधिकारी का कहना है, 'पिछले कुछ दिनों में यात्रा की काफी योजनाएं टाली गई हैं। इस वक्त विदेश यात्रा करने वाले हमारे ज्यादातर यात्री यूरोपीय देशों या अमेरिका से हैं जो भारत यात्रा से वापस लौट रहे हैं या वैसे भारतीय शामिल हैं जो अमेरिका में लंबे समय तक के लिए या वर्क वीजा के साथ जा रहे हैं। जिन्हें कारोबार के मकसद से कुछ दिनों के लिए विदेश जाना था वे अपनी बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं। घरेलू फ्लाइट में भी विदेशी पर्यटकों की तादाद घट रही है क्योंकि कंपनियों के काम के मकसद से होने वाली यात्रा में कटौती की गई है। अगले दो हफ्ते भी अहम हैं क्योंकि हम आगे भी यात्रा में कटौती की गुंजाइश देख रहे हैं।' मांग में कमी की वजह से विमानन कंपनियां फ्लाइट रद्द कर रही हैं या फिर उन देशों में सेवाएं दे रही हैं जहां कोरोनावायरस के कम मामले हैं। एशियाई और यूरोपीय विमानन कंपनियों में कई अधिकारी वेतन कटौती करने के लिए मजबूर हो गए हैं। इक्सिगो के सह संस्थापक और सीईओ आलोक वाजपेयी कहते हैं, 'अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर भी विमान किराये में 30-35 फीसदी तक की कमी आई है। विमान किराये में कटौती यात्रा चेतावनी जारी होने की वजह से है।' एमिरेट्स ने भारत से यूरोप, मॉरिशस और सेशेल्स की यात्रा के लिए 13 मार्च से 20 नवंबर के बीच 10 फीसदी छूट देने की घोषणा की है।

आयाटा ने कहा, विमानन क्षेत्र की कमाई पर इस साल 113 अरब डॉलर का पड़ेगा असर

गहराता जा रहा संकट

अमेरिका में कोरोनावायरस से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। अमेरिकी कांग्रेस में सांसद तेजी इस संक्रामक रोग से लड़ने के लिए 8 अरब डॉलर से अधिक की राशि देने के लिए तैयार हो गए हैं। कैलिफॉर्निया तट पर भी एक क्रूज जहाज पर यात्रियों और चालक दल के सदस्यों में वायरस संक्रमण के लक्षण दिखने के बाद हजारों लोग जहाज पर फंस गए हैं।

दक्षिण कोरिया में कोरोनावायरस के 760 नए मामले सामने आने के बाद इसके कुल मामलों की संख्या गुरुवार को 6,088 हो गई। देश में अब तक इस वायरस से 37 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में भी वायरस से मरने वालों का आंकड़ा बुधवार को 100 के पार पहुंच गया और संक्रमण की चपेट में आने वाले व्यक्तियों की संख्या तीन हजार से ज्यादा हो गई है।

कोरोनावायरस का संदिग्ध मामला सामने आने के बाद ईसा मसीह के जन्म स्थान बेथलहम में बने चर्च को बंद कर दिया गया है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्री ने गुरुवार को कहा कि कोरोनावायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए वे कागजी मुद्रा का कम से कम इस्तेमाल करें क्योंकि नोटों का लेन-देन वायरस फैलने में मदद कर रहा है। ईरान में अभी तक कम से कम 92 लोगों की मौत हुई है और 2,922 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है।

वायरस के बढ़ते खतरे के डर से स्कूलों को बंद किए जाने से वैश्विक स्तर पर करीब 30 करोड़ छात्रों को कई हफ्ते से घरों में ही रहना पड़ रहा है। इससे इनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। चीन में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 3000 के पार पहुंच गई है जबकि कुल संक्रमित लोगों की तादाद 80,400 से ज्यादा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि दुनिया भर में कोविड-19 से संक्रमित करीब 3.4 प्रतिशत लोगों की मौत हो गई। *एजेंसियां*

बैंकॉक में एक छात्रा की जांच करता स्वास्थ्यकर्मी

देश में दवा-एपीआई की कमी नहीं: गौड़ा

विनय उमरजी

कोरोनावायरस को लेकर बढ़ी चिंता के बीच केंद्रीय रसायन एवं दवा मंत्री डी वी सदानंद गौड़ा ने गुरुवार को कहा कि दवा निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री (एपीआई) और दवा की कमी नहीं है। फिक्की द्वारा आयोजित 'इंडिया फार्मा 2020' कार्यक्रम में गौड़ा ने बताया, 'दवाओं की उपलब्धता और आपूर्ति को लेकर कुछ भ्रम जैसी स्थिति है। हमारे पास पर्याप्त दवाएं और एपीआई है। विनिर्माताओं के लिए तीन महीने तक कोई कमी जैसी स्थिति नहीं है।' उन्होंने दवा बनाने की सामग्री के लिए चीन पर बढ़ी निर्भरता के सवाल पर यह जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मंत्रिसमूह का गठन किया है जो हालात पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने घोषणा की है कि केंद्र ने गुजरात में एक एपीआई पार्क और एक मेडिकल उपकरण पार्क बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

उन्होंने बताया कि सरकारी और निजी अस्पताल भी वायरस संक्रमण रोकने के लिए तैयार हैं।' गौड़ा ने कहा कि देश का दवा उद्योग 100 अरब डॉलर के स्तर पर जबकि मेडिकल उपकरण क्षेत्र 2025 तक 50 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच सकता है।

मास्क, सैनिटाइजर की ऑनलाइन बढ़ रही मांग

पीरजादा अबरार

कोरोनावायरस संक्रमण से जुड़े मामले बढ़ने के साथ ही ई-कॉमर्स कंपनियों मसलन ईबे, फ्लिपकार्ट और एमेजॉन पर सैनिटाइजर, मास्क और विषाणुनाशकों की मांग में तेजी आई है। यह मांग न केवल भारत बल्कि अमेरिका और यूरोप तथा पश्चिम एशिया के देशों से भी की जा रही हैं। उद्योग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इनमें से ज्यादातर उत्पाद आउट ऑफ स्टॉक हैं। अमेरिका के मुख्यालय वाली ई-कॉमर्स कंपनी ईबे इंडिया के कंट्री मैनेजर विद्मय नैनी ने बताया, 'पिछले पखवाड़े में मास्क, सैनिटाइजर और कई स्वास्थ्य से जुड़े सामानों का निर्यात करते हुए हमने अच्छा कारोबार किया है। स्वास्थ्य सेगमेंट में तिगुने अंक की वृद्धि रही है।' ईबे से भारत में एक लाख से ज्यादा विक्रेता जुड़े हैं। उद्योग के अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि ग्राहक चीन से आने वाले सामान नहीं ले रहे हैं ऐसे में भारतीय विक्रेताओं के सामने अच्छा मौका है जिसे वे भुना सकते हैं।

एमेजॉन और वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली कंपनी फ्लिपकार्ट पर भी इन उत्पादों की मांग ज्यादा देखी जा रही है। ई-कॉमर्स उद्योग से जुड़े एक अधिकारी ने बताया, 'माल खत्म हो गया है और विक्रेता अब मेडिकल स्टोर तक भी आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं।' देश में एन95 मास्क बनाने वाले निर्माताओं को भी इन्हें बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने इस साल की शुरुआत में इनके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था।

तकनीकी उद्योग में पुर्जों की किल्लत होगी दूर

भारत सरकार अपने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को सहारा देने पर विचार कर रही है। वह इस क्षेत्र में पुर्जों की किल्लत दूर करने के लिए इन्हें चीन से हवाई मार्ग के जरिये मंगाने की योजना बना रही है। तीन सरकारी अधिकारियों ने कहा कि वे चीन में फैले कोरोनावायरस के संकट से इस क्षेत्र को बचाने के प्रयास में जुटे हैं। इनमें से दो अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन उद्योग लॉबी समूहों से चीन में तैयार होने वाले उन पुर्जों की सूची तैयार करने के लिए कहा है जिन्हें सरकार वहां से हवाई मार्ग के जरिये मंगा सकती है। चीन में बाजार लंबे समय तक बंद रहने के बाद अब धीरे धीरे खुलने शुरू हो गए हैं लेकिन वह अभी भी बहुत सारी वस्तुओं के उत्पादन और आपूर्ति में देरी से जूझ रहा है। आर्थिक सुस्ती का सामना कर रहे भारत के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण खासकर स्मार्टफोनों को असेंबल करने का कारोबार एक उभरता हुआ क्षेत्र है। लेकिन इस क्षेत्र में अभी भी भारत कैमरा मॉड्यूल और डिस्पले स्क्रीन जैसे पुर्जों के लिए चीन पर काफी ज्यादा निर्भर है।

दूसरे उद्योग भी हवाई मार्ग से माल मंगाने के विकल्प की गुंजाइश तलाश रहे हैं। इस मामले के जानकार एक सूत्र ने कहा कि द ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपने सदस्यों से संपर्क कर इसका आकलन करने के लिए कहा है कि किन कलपुर्जों की कमी हो रही है और किन्हें हवाई मार्ग से मंगाया जा सकता है। भारत का वाहन उद्योग इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों, दबाव सेंसर और ईंधन इंजेक्ट करने वाले

पुर्जों जैसे कलपुर्जों के लिए काफी ज्यादा चीन पर भरोसा करता है। एक सरकारी सलाहकार ने कहा कि चीन से औषधि घटकों को हवाई मार्ग से भेजने के लिए भी वहां भारतीय दूतावास सक्रिय है। एक सरकारी सूत्र ने कहा, 'इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन के पुर्जों के लिए प्रौद्योगिकी मंत्रालय विमानन कंपनियों और हवाई मालवाहकों के संपर्क में है और वे उद्योग से जुड़े रहे हैं।' अधिकारी ने कहा कि चीन के ग्वांगचाऊ और शांघाई से पुर्जों को हवाई मार्ग से मंगाने के विकल्प पर चर्चा हो रही है। सूत्रों ने इस बारे में कुछ नहीं बताया कि यह प्रक्रिया कब से शुरू होगी।

इस बारे में प्रतिक्रिया देने के लिए अनुरोध किए जाने पर विमानन मंत्रालय ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चीन में ट्रक ड्राइवरों की कमी, सड़कों पर चेकप्वाइंट के बढ़ने और चीन के बंदरगाहों पर कामगारों की कमी के कारण वहां अभी भी जिन कलपुर्जों का उत्पादन हो रहा है उनकी ढुलाई भी धीमी पड़ गई है। *एजेंसियां*